घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 275- बुधवार 05- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मानसून सत्र : संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हंगामा...

खड़गे बोले...ईडी कहां है,रिजिजू ने कहा...विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में दो बार स्थगित हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित भी हो गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई,लेकिन 20 मिनट ही चल पाई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा- राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ईडी,सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं। सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए।

वित्त मंत्री सीतारमन ने शोर-शराबे के बीच बिल पेश किया

मंगलवार को दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। पीठासीन दिलीप सैकिया ने इन सांसदों को नारे न लगाने और बैठ जाने के लिए कहा लेकिन वे नहीं माने। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ (संशोधन) बिल पेश किया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए।

खड़गे बोले...सरकार चंदा चोरी पर जवाब दे,रिजिजू ने कहा...विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा : राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कैश, चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। संसद में इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। खड़गे ने कहा- पीएम ने ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी और वे राम मंदिर के हर महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होते रहे हैं। खड़गे ने सवाल किया कि ईडी,सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं। सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए।

विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन
प्रियंका बोलीं...भाजपा से ऊब चुकी जनता

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस,समाजवादी पार्टी,राजद और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जवाबदेही की मांग की। संसद भवन परिसर में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा,समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव,अवधेश प्रसाद,राजद सांसद मनोज झा,संजय यादव,कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन,कर्मवीर बौद्ध सहित कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने एक पोस्टर हाथ में ले रखा था,जिस पर लिखा था,भाजपा ने किया राम का अपमान,दान चोरी पर कब दोगे बयान। कई सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ लिखे पोस्टर भी प्रदर्शित किए। कांग्रेस सांसदों ने एक बड़ा पोस्टर हाथ में लेकर सवाल किया,अमित शाह संसद से गायब क्यों? विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रतीकात्मक रूप से एक दानपात्र भी रखा, जिसमें कई सांसदों ने विरोध स्वरूप चंदा डाला। प्रदर्शन के दौरान शेम-शेम के नारे भी लगाए गए और सरकार से राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी पर जवाब देने की मांग की गई। इस बीच मध्यप्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी से थक चुकी है और उपचुनाव के नतीजे इसकी शुरुआत हैं।

विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 राज्यसभा से पारित

राज्यसभा ने मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक,2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत दो वर्ष से अधिक की देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अनिवार्य किया गया है। दो बार सदन की कार्यवाही आज स्थगित होने के बाद दोपहर 02 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय को विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हुए उपाध्यक्ष ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति दी। खरगे ने कहा कि सदन में अनुशासन बनाए रखने का एकमात्र तरीका प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का सदन में आकर बयान देना है। उन्हें सदन में आना चाहिए। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। उपसभापति ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को विधेयक पर चर्चा के लिए बोलने का मौका दिया। नेताम ने कहा कि यह विधेयक गृह मंत्रालय से संबंधित है इसलिए गृहमंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए। इसके बाद उन्हें बीच में ही रोक कर उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद दर्शना सिंह को बोलने का मौका दिया।

चेन्नई में बवाल...तृषा पर कमेंट को लेकर उदयनिधि स्टालिन को घर से उठा ले गई पुलिस

उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे बाद रिहा...सीएम विजय की करीबी एक्ट्रेस तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

चेन्नई,04 अगस्त 2026। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु पुलिस ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उदयनिधि सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में भी मौजूद थे। इसी दौरान भीड़ में 'तृषा,तृषा' के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उदयनिधि ने कहा,'पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे,वहां जरूर पहुंचना चाहिए।' बाद में सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि,उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया।

तमिलनाडु की भाजपा इकाई के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने एक्स पर कहा कि उदयनिधि की कथित'डबल मीनिंग'टिप्पणी'घृणित,अश्लील, आपत्तिजनक और शर्मनाक' है। भाजपा नेता ने कहा, ''सचमुच,कोई बदमाश या चोर भी,जिसकी मां, पत्नी या बेटी हो,इतनी अभद्र भाषा में बात नहीं करेगा। कोई भी मां,पत्नी या बेटी ऐसी टिप्पणी करने वालों को माफ नहीं करेगी।'उन्होंने कहा था कि इस टिप्पणी के लिए उदयनिधि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। टीवीके विधायक रेवंत चरण ने भी इस बयान को घटिया बताया था और कहा थि कि जानबूझकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जब कावेरी मामले में उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं मिला तो वह घटिया भाषा का इस्तेमाल करने लगे।

केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला,पुलिस ने रोका

फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठे,बोले-ई20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां भिजवाईं

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई20 फ्यूल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकला। हालांकि,दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल,मनीष सिसोदिया,जैस्मिन शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल सहित अन्य आम आदमी पार्टी नेता फिरोजशाह रोड पर ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने करीब 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यह मार्च निकाला था। पार्टी का दावा है कि उसने देशभर से 2.30 लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई हैं। मार्च के दौरान केजरीवाल ने कहा कि ई20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, जिन्हें वे खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे लेकिन हमें पुलिस ने रोक दिया। हमने सभी चिट्ठियां पुलिस के हाथों मोदी जी को भेज दी हैं। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा...हमें उम्मीद है कि पीएम हमसे मिलेंगे।

केजरीवाल बोले...ई20 रोकने के लिए नीट से बड़ा आंदोलन करना होगा : ई20 के विरोध में धरने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ट्रम्प के दबाव में मोदी सरकार अमेरिका से एथनॉल खरीद रही है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा एथनॉल बनाता है और उसने भारत पर इसे खरीदने का दबाव बनाया। केजरीवाल ने कहा- अमेरिका का कचरा खरीदकर हमारी 30 लाख गाड़ियों पर थोपा जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें नीट आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना होगा। उन्होंने लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ई20 नीति के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

आम आदमी पार्टी बोली... प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी ज्ञापन लेने यहां आए : दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा...हम 2 लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं लेकर आए हैं। हमें आगे जाने दिया जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी यहां आकर ज्ञापन ले ले और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए। सौरभ भारद्वाज ने भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा- इतनी बड़ी संख्या में पुलिस, [illegible], लाठियां और ढाल देखकर हैरानी हो रही है। हम सिर्फ लोगों की चिट्ठियां प्रधानमंत्री तक पहुंचाने आए हैं।

एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी,17 घायल

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया फ्लाइट एआई2379 मंगलवार को टर्बुलेंस, यानी तेज हवा के झटकों में फंस गई। अचानक 300 फीट तक नीचे आ गई। हालांकि, पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 11:30 बजे सुरक्षित उतार लिया। प्लेन में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी बताया कि घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स समेत 17 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ को दिल्ली एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर और 7 घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एअर इंडिया ने पहले बताया था कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने दावा किया कि उड़ान भरने के करीब डेढ़ घंटे बाद तेज झटके लगने लगे। सुबह का समय था और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अचानक विमान जोर से हिलने लगा और 2-3 मिनट तक पलटी खाता रहा। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इस घटना की जांच कर रहा है। यात्री के मुताबिक कुछ लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि 70 से 80% लोगों को मामूली चोट लगी हैं। फ्लाइट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें उसकी सीलिंग के पैनल में दरारें दिखीं। टर्बुलेंस का मतलब है हवा का बहाव अचानक बदल जाना, जिससे विमान को झटके लगने लगते हैं। इस दौरान विमान कुछ समय के लिए ऊपर-नीचे या दाएं-बाएं हिल सकता है और कभी-कभी कुछ फीट नीचे भी आ जाता है। इसी वजह से यात्रियों को लगता है कि विमान गिर रहा है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता।

डीजल लेकर जा रहा टैंकर बिजली के पोल से टकराया

लगी भीषण आग,3 लोगों की जिंदा जलकर मौत

आजमगढ़,04 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गोरखपुर से डीजल लेकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप की ओर जा रहा एक भारी-भरकम टैंकर जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर स्थित बिजली उपकेंद्र (सब-स्टेशन) के पास एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। बेकाबू टैंकर बिजली के पोल से जा टकराया, जिससे पोल पर लगा ट्रांसफार्मर सीधा टैंकर पर गिर गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसमें भीषण आग लग गई। हादसा इतना खौफनाक था कि धमाके के तुरंत बाद टैंकर से आग की ऊंची-ऊंची और विकराल लपटें उठने लगीं। आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर चाहकर भी टैंकर के पास नहीं जा सके और उन्हें दूर से ही इस भयावह मंजर को देखने पर मजबूर होना पड़ा। देखते ही देखते आग ने पूरे टैंकर को अपनी आगोश में ले लिया और उसमें मौजूद लोगों को बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं।

डोंगरगढ़ बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी

पंकज अग्रवाल ने अपना पद छोड़ा...

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। डोंगरगढ़ भाजपा में पिछले कुछ समय से चल रहा संगठनात्मक असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सामने आ रहे इस्तीफों ने पार्टी की स्थानीय इकाई में हलचल बढ़ा दी है। पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के इस्तीफे चर्चा का विषय बने,वहीं अब भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की नई जिला कार्यकारिणी घोषित होने के अगले ही दिन डोंगरगढ़ मंडल के सह-संयोजक पंकज अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस नए घटनाक्रम ने संगठन के भीतर चल रही गतिविधियों और संभावित असंतोष को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है। पंकज अग्रवाल ने भाजपा जिलाध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफा पत्र में बताया कि वे लंबे समय से भाजपा आईटी सेल में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वर्तमान में व्यक्तिगत और व्यावसायिक दायित्वों के कारण वे संगठन को अपेक्षित समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने भाजपा आईटी सेल की जिम्मेदारियों के साथ-साथ पार्टी के सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में उन्होंने पार्टी नेतृत्व द्वारा मिले अवसर, मार्गदर्शन और विश्वास के लिए आभार भी व्यक्त किया। पंकज अग्रवाल के इस्तीफे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने पत्र में किसी भी नेता,पदाधिकारी या संगठन के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका निर्णय पूरी तरह निजी और व्यावसायिक कारणों से जुड़ा हुआ है। हालांकि, उनका इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है जब डोंगरगढ़ भाजपा पहले से ही लगातार आंतरिक असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में उनके इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।

डाबर के '100% शुद्ध' दावे वाले प्रोडक्ट पर रोक : फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शहद-घी समेत कई सामान बेचना बैन किया,15 दिन में रिपोर्ट मांगी...

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। डॉबर के कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने-पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाई है। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया है। इस पर डाबर से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सोमवार 3 अगस्त को फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है।

फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे पाए गए थे। इनमें '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% प्योरिटी गारंटेड', '100% ऑर्गनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे लेबल शामिल थे।

फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि '100 प्रतिशत' दावों का यह उपयोग एफएसएस विनियम, 2018 का उल्लंघन करता है। ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।

छात्रों को माफ करने के बारे में प्रधानमंत्री के विचार देश के बहुलतावादी स्वरूप के विपरीत : राहुल गांधी

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि निष्पक्ष परीक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को माफ करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार देश के बहुलतावादी स्वरूप के विपरीत है। राहुल गांधी यहां कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) के महासचिव वाइको के संसदीय भाषणों के संकलन 'वाइको इन पार्लियामेंट' के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एमए बेबी, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे।राहुल गांधी ने कहा कि देश एक अजीब दौर से गुजर रहा है, जहां छात्र निष्पक्ष परीक्षाओं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं।

सीबीएसई का तीन भाषा नियम सुप्रीम कोर्ट में फंसा! छात्रों के भविष्य पर क्या होगा फैसला?

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सीबीएसई की कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू तीन-भाषा नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, इसलिए मामले की सुनवाई बुधवार या गुरुवार को की जाए। इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम देखेंगे। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सीबीएसई की नई भाषा नीति लागू हो चुकी है।

'मंगल मिलन' बैठक में पीएम मोदी सहित एनडीए नेताओं ने बनाई संसद की रणनीति,एफटीए और मत्स्य क्षेत्र पर हुए प्रजेंटेशन

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक में संसद के मौजूदा सत्र, विधायी कामकाज और विपक्ष के विरोध के बीच गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और एनडीए के विभिन्न घटक दलों के सांसद उपस्थित रहे।

पीयूष गोयल ने एफटीए पर दिया प्रजेंटेशन : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत द्वारा हाल में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों और उनके रणनीतिक महत्व पर प्रस्तुति दी। उन्होंने सांसदों को व्यापार समझौतों से निर्यात, निवेश, रोजगार और वैश्विक बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की जानकारी दी। बैठक में सांसदों से इन समझौतों के प्रमुख बिंदुओं को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने को कहा गया।

मत्स्य क्षेत्र की योजनाओं पर दी जानकारी : केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मत्स्य क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और भविष्य के रोडमैप पर जानकारी दी। उन्होंने मछुआरों के कल्याण, मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, आधारभूत संरचना विकसित करने और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि के लिए संचालित कार्यक्रमों का विवरण रखा।

किरण रिजिजू ने सांसदों को किया संबोधित

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी और विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में सदन के भीतर समन्वय बनाए रखने, महत्वपूर्ण विधेयकों पर गठबंधन का पक्ष मजबूती से रखने और विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा होने की जानकारी है।

संपादकीय

आरक्षण पर टिप्पणी नहीं,संविधान पर आस्था की कसौटी है यह मामला

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संवैधानिक विषयों पर सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को निजी राय व्यक्त करते समय अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए?

विवाद बढ़ने के बाद संबंधित अधिकारी ने पोस्ट हटा दी और खेद भी व्यक्त किया। लेकिन अब बहस केवल एक पोस्ट तक सीमित नहीं रह गई है। विपक्ष इसे आरक्षण और संविधान के सम्मान से जोड़ रहा है,जबकि सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह स्पष्ट करे कि ऐसे मामलों में उसकी नीति और जवाबदेही क्या होगी।

आरक्षण कोई राजनीतिक दल की देन या किसी सरकार की कृपा नहीं है। यह भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने का एक संवैधानिक प्रावधान है। इस विषय पर मतभेद हो सकते हैं,न्यायालयों में बहस हो सकती है,नीतिगत समीक्षा की मांग भी उठ सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस पर होने वाली टिप्पणी मर्यादित, जिम्मेदार और संवेदनशील होनी चाहिए।

विशेष रूप से तब,जब टिप्पणी करने वाला व्यक्ति किसी सरकारी विभाग का अधिकारी हो। सरकारी सेवक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त नहीं होती,लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद की गरिमा, सेवा नियमों और सार्वजनिक विश्वास का ध्यान रखे। क्योंकि उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी भी कई बार पूरे विभाग या सरकार के दृष्टिकोण के रूप में देखी जाने लगती है। दूसरी ओर, किसी विवादित पोस्ट के सामने आने के बाद केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी समाधान नहीं है। यदि वास्तव में सेवा नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि केवल भूल हुई है, तो उसके अनुरूप कार्रवाई हो। लेकिन निर्णय तथ्यों और नियमों के आधार पर होना चाहिए,न कि केवल जनदबाव या राजनीतिक दबाव के आधार पर।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों को सामाजिक तनाव पैदा करने का माध्यम न बनाया जाए। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है,लेकिन संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। सरकार की जिम्मेदारी केवल विवाद शांत कराने की नहीं,बल्कि यह भरोसा दिलाने की भी है कि उसके अधिकारी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे। वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी केवल विरोध दर्ज कराने की नहीं,बल्कि इस विषय पर समाज में तथ्यपरक और संयमित संवाद बनाए रखने की भी है।

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सार्वजनिक पद केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। सोशल मीडिया पर लिखे गए कुछ शब्द कभी-कभी वर्षों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देते हैं।

आरक्षण पर बहस हो सकती है,लेकिन संविधान के प्रति सम्मान पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

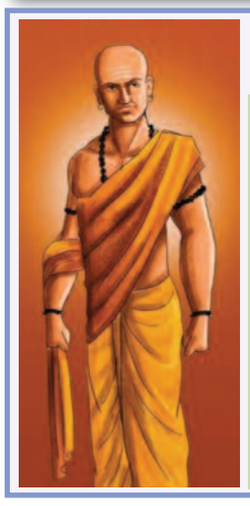

सुविचार

कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से तीन प्रश्न कीजिए मैं यह क्यों कर रहा हूं इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े – चाणक्य

बांकीपुर का संदेश : क्या बिहार की राजनीति में शुरू हो चुका है नया अध्याय,या यह सिर्फ एक उपचुनाव का असर है?

भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में प्रशांत किशोर की जीत ने बदले राजनीतिक विमर्श,अब सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव का

रवि सिंह
कोरिया,छत्तीसगढ़

प्रकाशक: दैनिक घटती घटना

बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित घटनाओं और नए राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोग शाला रही है,कभी समाजवाद की राजनीति ने यहां नई दिशा दी, कभी मंडल आंदोलन ने सत्ता का चेहरा बदल दिया,तो कभी सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार ने दो दशकों तक सत्ता पर पकड़ बनाए रखी,अब वर्ष 2026 के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक नया राजनीतिक अध्याय जोड़ दिया है,यह केवल एक उप चुनाव नहीं रहा,बल्कि उस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है,जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से हो रही थी,जिस व्यक्ति को देश अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता था,वही अब जनता के वोट से विधान सभा पहुंच चुका है,प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज के टिकट पर बिहार विधानसभा में प्रवेश कर यह साबित कर दिया कि केवल दूसरों की राजनीति लिखने वाले रणनीतिकार ही नहीं,बल्कि स्वयं भी जनादेश प्राप्त कर सकते हैं,लेकिन इस परिणाम को केवल प्रशांत किशोर की जीत मान लेना भी अधूरा विश्लेषण होगा,यह परिणाम भाजपा के लिए भी एक राजनीतिक संदेश है और बिहार की पूरी राजनीति के लिए भी।

बांकीपुर क्यों था इतना महत्वपूर्ण?-बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में गिनी जाती है,राजधानी पटना के मध्य स्थित यह सीट केवल शहरी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती,बल्कि इसे भाजपा की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता रहा है,पिछले लगभग तीन दशकों में भाजपा ने इस सीट पर लगातार अपना वर्चस्व बनाए रखा,कई चुनावों में पार्टी का मत प्रतिशत 60 से 80 प्रतिशत तक पहुंचा,यही कारण था कि राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह धारणा बन गई थी कि बांकीपुर भाजपा का अभेद्य किला है।

यही आंकड़े बताते हैं कि जिस सीट पर भाजपा वर्षों से निर्विवाद रूप से जीतती आ रही थी, उसी सीट पर इस बार जन सुराज ने जीत दर्ज कर इतिहास बदल दिया।

भाजपा के एक निर्णय ने बदल दिया पूरा राजनीतिक समीकरण-राजनीति में कई बार विरोधी दल से अधिक अपने निर्णय चुनाव की दिशा तय कर देते हैं,बांकीपुर सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस सीट से विधायक रहे नितिन नवीन को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली,उनके इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हुआ,यदि यह सीट रिक्त नहीं होती तो संभवतः प्रशांत किशोर को विधानसभा में प्रवेश के लिए किसी अन्य अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती, लेकिन राजनीति अवसरों का खेल है और प्रशांत किशोर ने इस अवसर को ऐतिहासिक जीत में बदल दिया,कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे भाजपा की रणनीतिक मजबूरी मानते हैं,लेकिन परिणाम ने यह भी दिखाया कि कोई भी राजनीतिक गढ़ स्थायी नहीं होता।

रणनीतिकार से जनप्रतिनिधि बनने तक का सफर-प्रशांत किशोर का राजनीतिक जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है,उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार,ममता बनर्जी और कई अन्य नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई। चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी, लेकिन जब उन्होंने स्वयं राजनीति में उतरने का निर्णय लिया,तब शुरुआती परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन सुराज राज्यभर में चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी, आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि चुनावी रणनीति बनाना और स्वयं चुनाव जीतना दो अलग बातें हैं,लेकिन बांकीपुर ने यह धारणा बदल दी। इस जीत ने यह संदेश दिया कि प्रशांत किशोर केवल राजनीतिक सलाहकार नहीं रहे,बल्कि अब वे जनता से सीधा जनादेश लेने वाले नेता भी बन चुके हैं।

क्या भाजपा का जनाधार कमजोर हो रहा है?-यह प्रश्न स्वाभाविक है क्योंकि भाजपा ने अपने सबसे मजबूत माने जाने वाले शहरी गढ़ों में से एक खोया है,हालांकि किसी भी उपचुनाव के परिणाम को पूरे राज्य का जनादेश मान लेना राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा,उपचुनाव अक्सर स्थानीय परिस्थितियों,प्रत्याशी की लोकप्रियता, संगठन की सक्रियता और सत्ता विरोधी भावना से प्रभावित होते हैं,फिर भी बांकीपुर का परिणाम भाजपा के लिए निश्चित रूप से आत्ममंथन का विषय है, यदि सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर भी पार्टी हारती है, तो यह संगठन और नेतृत्व दोनों के लिए चेतावनी का संकेत माना जाएगा।

सबसे बड़ी राजनीतिक क्षति किसकी हुई?-इस उपचुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान केवल भाजपा का नहीं माना जा सकता,राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे पारंपरिक विपक्षी दल पूरे चुनाव में लगभग हाशिए पर दिखाई दिए,चर्चा भाजपा और जन सुराज के बीच केंद्रित रही,इससे यह संकेत भी मिलता है कि बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावनाओं पर अब गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है, यदि आने वाले समय में भाजपा विरोधी मतों का बड़ा हिस्सा जन सुराज की ओर जाता है, तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है।

क्या अब बिहार को नया राजनीतिक ध्रुव मिल गया है?-पिछले तीन दशकों से बिहार की राजनीति मुख्यतः दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है–एक ओर भाजपा और उसके सहयोगी,दूसरी ओर राजद और उसके सहयोगी,प्रशांत किशोर की जीत ने तीसरे राजनीतिक विकल्प की संभावना को मजबूत किया है,लेकिन किसी भी नई पार्टी को स्थायी राजनीतिक ताकत बनने के लिए केवल एक सीट नहीं,बल्कि पूरे राज्य में संगठन,नेतृत्व और जनाधार विकसित करना पड़ता है,इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जन सुराज बिहार की मुख्य राजनीतिक शक्ति बन चुकी है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसने अपनी उपस्थिति प्रभावी ढंग से दर्ज करा दी है।

अब असली परीक्षा विधानसभा के भीतर होगी- चुनाव जीतना पहला चरण है, जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभाव छोड़ना दूसरा,अब बिहार की जनता यह देखेगी कि प्रशांत किशोर विधानसभा के भीतर किस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्या वे केवल सरकार की आलोचना तक सीमित रहेंगे या शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार,उद्योग,कृषि और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर ठोस वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करेंगे? यदि वे सदन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, तो उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और बढ़ सकती है।

2027 का ट्रेलर या केवल एक उपचुनाव?-बिहार की राजनीति में अक्सर उपचुनावों को भविष्य का संकेत माना जाता है,लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि हर उपचुनाव अगले विधानसभा चुनाव का परिणाम तय नहीं करता,फिर भी बांकीपुर का परिणाम यह स्पष्ट करता है कि बिहार का मतदाता नए विकल्पों को सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार है,यदि जन सुराज इस जीत को संगठन विस्तार में बदल पाती है, तो 2027 का चुनाव पहले की तुलना में कहीं अधिक रोचक और बहुकोणीय हो सकता है।

बांकीपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास

वर्ष	विजेता	मत प्रतिशत (लगभग)	उपविजेता
1995	भाजपा	40.7%	जनता दल
2000	भाजपा	54.9%	राजद
फरवरी 2005	भाजपा	69.1%	राजद
अक्टूबर 2005	भाजपा	69.3%	कांग्रेस
2006 (उपचुनाव)	भाजपा	82.3%	कांग्रेस
2010	भाजपा	72.1%	राजद
2015	भाजपा	60.2%	कांग्रेस
2020	भाजपा	59.1%	कांग्रेस
2025	भाजपा	62.7%	राजद
2026 (उपचुनाव)	**जन सुराज**	**49.4%**	**भाजपा (34.5%)**

संदेश केवल जीत का नहीं,बदलाव की संभावना का है...

बांकीपुर उपचुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति में कोई भी किला स्थायी नहीं होता,भाजपा के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का अवसर है,जबकि प्रशांत किशोर के लिए यह राजनीतिक जीवन की वास्तविक शुरुआत है, यह जीत बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना अवश्य पैदा करती है,लेकिन उस बदलाव को स्थायी रूप देने के लिए केवल एक उपचुनाव पर्याप्त नहीं होगा,आने वाले वर्षों में संगठन, जनसंपर्क, वैकल्पिक नीतियां और विधानसभा के भीतर प्रदर्शन ही तय करेंगे कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के नए केंद्र बनते हैं या बांकीपुर केवल उनके राजनीतिक सफर का एक यादगार पड़ाव बनकर रह जाता है, लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक होती है,बांकीपुर ने एक संकेत दिया है,अंतिम फैसला अभी बिहार की जनता के हाथ में है।

देश नशा-मुक्त हो या न हो,नारे ज़रूर नशा-मुक्त हैं...

***अभियान इतने सफल हैं कि नशा अब ऑनलाइन हो गया है**
***व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि नशा अब पहले से ज़्यादा सुलभ है...**

कानून की सबसे लंबी सजा कभी अपराधी को नहीं,न्याय को मिलती है। नशा मुक्त भारत का मौजूदा अभियान इसी सजा के बीच अपनी सफलता का उत्सव मना रहा है। सौ-सप्ताहीय कार्यक्रम, युवाओं की शपथ,जागरूकता यात्राएं और सरकारी संकल्प यह भरोसा जगाते हैं कि नशे के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर एनडीपीएस कानून से जुड़े लगभग 3.96 लाख मुकदमे अदालतों में वर्षों से लंबित हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं,बल्कि उस व्यवस्था का मौन बयान है,जहां न्याय की हर देरी अपराध का आत्मविश्वास बढ़ाती है। अभियान सक्रियता का आभास देते हैं,जबकि अदालतों की ठहरी हुई फाइलें बताती हैं कि व्यवस्था अपनी ही रफ्तार से हार रही है। नशा अब कानून से नहीं,कानून की देरी से सबसे अधिक सुरक्षित हो चुका है।

प्रो.रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

अदालतें जब समय हारने लगती हैं, तब अपराधी मुकदमे नहीं,अवसर गिनते हैं। पंजाब में लगभग साठ हजार और केरल में करीब पचास हजार एनडीपीएस मामले वर्षों से लंबित हैं। विशेष अदालतें जरूरत से कम हैं, न्यायाधीश सीमित हैं और मुकदमों की चाल इतनी सुस्त है कि अनेक आरोपी जमानत पर बाहर आकर अपना तंत्र फिर खड़ा कर लेते हैं। यहीं न्याय की देरी अपराध का सबसे विश्वसनीय संरक्षण बन जाती है। जितने अधिक मामले दर्ज होते हैं, उतना ही बैकलॉग बढ़ता है और उतना ही यह विश्वास गहराता है कि गिरफ्तारी अंत नहीं,केवल एक औपचारिक पड़ाव है। नशा मुक्त अभियान अपराध को सामाजिक अभिशाप बताते हैं, लेकिन न्यायिक विलंब उसी अभिशाप की उम्र बढ़ाता रहता है। यह ऐसा विरोधाभास है, जिसे अब कोई सरकारी उपलब्धि ढक नहीं सकती।

नशे का बाजार अब गलियों से निकलकर मोबाइल की स्क्रीन पर फल-फूल रहा है। इतिहास में पहली बार गली हार गई और स्क्रीन जीत गई। एन्क्रिप्टेड ऐप, डार्क वेब और सोशल मीडिया के बंद समूहों ने खरीद-बिक्री को इतनी गोपनीयता दे दी है कि ग्राहक को घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिन कॉलेजों में नशा विरोधी रैलियां निकलती हैं, वहीं के छात्र मोबाइल से सप्लायर तक पहुंच जाते हैं। पुलिस पुराने तस्करों को पकड़ती है, लेकिन तब तक डिजिटल दुनिया नए चेहरे तैयार कर चुकी होती है। हमारी कार्रवाई आज भी एनालॉग सोच में अटकी है, जबकि अपराध पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। यही फासला अभियानों को प्रतीक और नशे को सुविधा बना देता है। जब तकनीक ही अपराध का सबसे भरोसेमंद माध्यम बन जाए,तब पोस्टर और शपथ उसकी रफ्तार नहीं रोक सकते।

जब ईमानदार श्रम की कीमत घटने लगे और जोखिम सबसे लाभकारी रोजगार बन जाए,तभी अपराध कारोबार बन जाता है। बेरोजगारी, त्वरित कमाई का आकर्षण और फैलता अवैध धन युवाओं को नशे की सप्लाई चेन में खींच लाता है। छोटे वाहक गिरफ्तार होते हैं,उनके परिवार बिखरते हैं और समाज उन्हें अपराध का चेहरा मान लेता है। उधर बड़े तस्कर कमजोर अभियोजन,लंबी कानूनी प्रक्रिया और तकनीकी खामियों की आड़ में बच निकलते हैं। अभियान युवाओं को नैतिकता का उपदेश देते हैं,लेकिन व्यवस्था सम्मानजनक आर्थिक विकल्प नहीं दे पाती। नशा केवल लत नहीं, कुछ परिवारों की छिपी आजीविका बन जाता है। जब तक यह आर्थिक सच स्वीकार नहीं किया जाएगा, हर अभियान बीमारी नहीं, उसके लक्षणों का उपचार करेगा।

आंकड़े कभी-कभी ऐसी जीत का उत्सव मनाते हैं, जिसे सच्चाई चुपचाप हार में बदल चुकी होती है। हर वर्ष प्रवर्तन एजेंसियां बड़ी जब्तियों का दावा करती हैं। मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और इसे सफलता बताया जाता है। लेकिन इतनी बरामदगी के बाद भी यदि बाजार में नशा पहले जैसी सहजता से उपलब्ध है और कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव नहीं आता,तो स्पष्ट है कि एक सप्लाई लाइन की जगह दूसरी खड़ी हो चुकी है। तब बरामदगी उपलब्धि नहीं,बल्कि लगातार रास्ते बदलते विशाल नेटवर्क का प्रमाण बन जाती है। जब्ती के आंकड़े जितने बढ़ते हैं, प्रश्न उतना बड़ा होता है कि उपलब्धता क्यों नहीं घट रही। सफलता की असली कसौटी बरामद माल नहीं, घटती मांग और कठिन होती पहुंच होनी चाहिए।

श्रावण मास की महिमा और सनातन संस्कृति की दिव्यता,हमारी आस्था का अमर स्पंदन

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

सनातन संस्कृति में काल गणना केवल समय का बोध नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और परमात्मा के बीच के गहन तादात्म्य का उत्सव है। इन उत्सवधर्मी महीनों में श्रावण मास(सावन का महीना) का स्थान सर्वोपरि और अत्यंत पावन माना गया है। यह मास केवल एक ऋतु का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन, प्रकृति के पुनरुद्धार और हमारी शाश्वत आस्था का जीवंत प्रतीक है।

प्रकृति का शृंगार और सृजन का उल्लास

श्रावण मास का आगमन ग्रीष्म ऋतु की तपन से त्रस्त धरती पर अमृत वर्षा लेकर आता है। जब आषाढ़ की उमस के बाद आसमान बादलों से घिरता है और मूसलाधार वर्षा होती है,तब प्रकृति मानो नई देह धारण कर लेती है।

चतुर्दिक हरियाली,सूखी और बंजर भूमि पर दूब और घास की चादर बिछ जाती है, वृक्षों पर नए कोपले फूटते हैं और कल-कल करती नदियाँ उफान पर होती हैं।

पंचतत्वों का संतुलन,यह मास हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार वर्षा प्रकृति की पिपासा को शांत कर उसमें नया जीवन फूंकती है, उसी प्रकार भक्ति की वर्षा हमारे अंतःकरण को सींचकर जीवन को ऊर्जावान बनाती है।

देवाधिदेव महादेव को समर्पित परम पवित्र मास

हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी मास में माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी।

महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक,इस पूरे मास में देवाधिदेव महादेव की आराधना का विशेष महत्व है। शिवालयों में ॐ नमः शिवाय के मंत्र गूंजते हैं और बेलपत्र,धतूरा, भांग तथा गंगाजल से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है।

सावन सोमवार का व्रत,हर सोमवार को रखे जाने वाले व्रत साधक को मानसिक शांति, संयम और अदम्य साहस प्रदान करते हैं। यह व्रत वासनाओं और विकारों पर नियंत्रण का संदेश देता है।

कांवड़ यात्रा,अटूट विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा

श्रावण मास की दिव्यता का सबसे विहंगम दृश्य देश के विभिन्न भागों में दिखाई देने वाली कांवड़ यात्रा है। भगवा वस्त्र धारण किए, नंगे पाँव मीलों की पैदल यात्रा करते हुए शिव भक्तों (कांवड़ियों) का यह समूह सनातन आस्था का सबसे प्रेरणादायक स्वरूप है।

कंठ में बम-बम भोले का उद्घोष और कंधे पर गंगाजल से भरे कांवड़ को उठाए ये भक्त बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं।

यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है,बल्कि यह समर्पण,अनुशासन, और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम,की जीवंत मिसाल है।

हमारी संस्कृति के उत्सव और लोक-पर्व

सावन का महीना केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है,बल्कि यह सामाजिक समरसता और लोक-संस्कृति का भी महाकुंभ है। नाग पंचमी,प्रकृति के हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हुए नाग देवता की पूजा की जाती है।श्रावणी पूर्णिमा (रक्षा बंधन),यह मास भाई-बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षा बंधन के साथ संपन्न होता है,जो सामाजिक बंधनों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। सावन के गीत और झूले,महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले कजरी,मल्हार और पेड़ों पर डाले जाने वाले झूले हमारी लोक-संस्कृति की जीवंतता और उल्लास के परिचायक हैं। श्रावण मास हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएँ और तपिश क्यों न आएँ, आस्था और प्रेम की फुहार हर संकट को पार करने की शक्ति देती है। यह मास हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने,आंतरिक शुद्धि प्राप्त करने और प्रकृति के साथ एकाकार होने का स्वर्णिम अवसर है।

जॉब नहीं तो सिंहासन हिलेगा,राहुल का प्रयागराज से बड़ा दांव

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ लिखा,जॉब नहीं मिलेगा,तो सिंहासन हिलेगा। यह पोस्ट ठीक उसी समय आया जब देश भर में बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। कोटा और देहरादून के बाद अब यह अभियान छात्रों की गूंज 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में उतरने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि मिस्ड कॉल और क्यूआर कोड के जरिए डेढ़ लाख से ज्यादा छात्रों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं,बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संकेत है। प्रयागराज कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मक्का माना जाता था। यहां हर साल देश-प्रदेश से लाखों युवा आते हैं। फॉर्म भरते हैं,फीस जमा करते हैं,सालों साल कोचिंग करते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक,रुकी हुई भर्तियां और परीक्षा पैटर्न में बदलाव ने इन युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। मई में करीब 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लीक की खबर आने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर जून में दोबारा परीक्षा हुई जिसमें करीब 20 लाख छात्र शामिल हुए। दो लाख के आसपास छात्र दोबारा नहीं बैठे। यह आंकड़ा बताता है कि कितने युवाओं का एक साल बर्बाद हो गया।दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए प्रदर्शन ने इस गुस्से को नया रूप दिया। जुलाई में जब हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े तो पुलिस ने लाठियां चलाईं और पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ। कई युवा घायल हुए। कुछ दिनों बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। लेकिन युवाओं का सवाल अभी भी वही है कि सिस्टम क्यों बार-बार नाकाम साबित होता है।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में ठीक यही बात दोहराई। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक ने युवाओं का आज छीन लिया, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल छीन लिया और दिल्ली में सिर्फ इसलिए लाठियां चलीं क्योंकि उन्होंने अपने हक की बात कही। अब बहाने नहीं चलेंगे। जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। केपी ग्राउंड पर मंच तैयार हो रहा है। आसपास के जिलों से छात्रों को लाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कौशांबी,प्रतापगढ़,अमेठी, रायबरेली,भदोही,मिर्जापुर, वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों से युवा आने वाले हैं। भदोही से अकेले हजारों छात्रों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं,बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को एक मंच देने की कोशिश है।उत्तर प्रदेश में युवा और बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की डबल इंजन सरकार रोजगार देने के दावे करती रही है। लेकिन पेपर लीक के मामले और भर्तियों में देरी ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्रों में ब्राह्मण,भूमिहार, मौर्य, कुर्मी और दलित समुदाय के युवा बड़ी संख्या में हैं। इनमें से कई पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ रहे हैं। लेकिन अगर ये युवा बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर झुकते हैं तो 2027 के समीकरण बदल सकते हैं।इतिहास गवाह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति ने देश को कई नेता दिए। चंद्रशेखर आजाद की शहादत की भूमि से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर,वीपी सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा तक की राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई। छात्र आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ जनमत बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता आया है।

राहुल गांधी का यह दौरा उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश लगता है।कोटा में 17 जून को अभियान शुरू हुआ था। देहरादून में 17 जुलाई को दूसरा चरण हुआ। अब प्रयागराज तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। पहले दिल्ली में 9 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित था,लेकिन अनुमति न मिलने के बाद इसे प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया।कांग्रेस की रणनीति साफ है। 2027 के चुनाव को जातिगत समीकरणों के बजाय युवा और बेरोजगारी के नैरेटिव पर केंद्रित करना। सपा के पीडीए फॉर्मूले के साथ अगर कांग्रेस छात्र शक्ति को जोड़ लेती है तो गठबंधन का आधार और मजबूत हो सकता है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर का असर कई राज्यों में दिख रहा है। ऐसे में प्रयागराज का कार्यक्रम सिर्फ स्थानीय नहीं,बल्कि राष्ट्रीय संदेश बन सकता है। डेढ़ लाख पंजीकरण का दावा अगर मैदान में भीड़ में तब्दील होता है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। प्रशासनिक अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और मौसम सब कुछ देखना होगा। पार्टी के अंदर भी तैयारियों को लेकर कुछ घर्षण की खबरें आई हैं। फिर भी अजय राय और स्थानीय नेता दावा कर रहे हैं कि केपी ग्राउंड से लेकर शहर की गलियां युवाओं से भर जाएंगी।राहुल गांधी के पोस्ट का स्वर आक्रामक है। सिंहासन हिलने की बात सिर्फ नारा नहीं, बल्कि युवाओं के गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

C M Y K

शिक्षा विभाग के संलग्नीकरण समाप्त करने के सरकारी दावों के बीच जारी आदेश पर उठे सवाल

क्या प्रशासनिक विवेक और शासन की मंशा में है विरोधाभास?

सुदामा राजवाड़े

बलरामपुर/रामानुजगंज,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन पिछले कई महीनों से शिक्षा विभाग में वर्षों से चली आ रही संलग्नीकरण (अटैचमेंट) व्यवस्था को समाप्त करने का अभियान चला रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने मूल कार्यस्थलों पर लौटेंगे तथा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी,इसी बीच बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से जारी एक आदेश ने प्रशासनिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है,जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में मूलतः प्रधान पाठक (हेडमास्टर) रहे मुन्ना लाल धुर्वे को जनपद पंचायत कुसमी का प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है,आदेश के अनुसार उन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, यह आदेश सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह निर्णय शासन की घोषित नीति की भावना के अनुरूप है अथवा केवल प्रशासनिक आवश्यकता के तहत लिया गया एक अस्थायी कदम है।

क्या कहता है आदेश?

31 जुलाई 2026 को जारी कलेक्टर कार्यालय के आदेश में उल्लेख है कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मुन्ना लाल धुर्वे,जो वर्तमान में प्रभारी क्षेत्र संयोजक,कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के रूप में कार्यरत हैं,उन्हें जनपद पंचायत कुसमी के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है,आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हें उक्त पद से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे तथा यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

मूल पद प्रधान पाठक,फिर प्रशासनिक दायित्वों की लंबी श्रृंखला

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मुन्ना लाल धुर्वे का मूल पद प्रधान पाठक है,वर्ष 2024 में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के माध्यम से उन्हें कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग में आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था,इसके बाद वर्तमान में वे सहायक आयुक्त कार्यालय में प्रभारी क्षेत्र संयोजक के रूप में कार्यरत हैं और अब उन्हें जनपद पंचायत कुसमी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है, यही तथ्य अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक शिक्षक संवर्ग के अधिकारी को लगातार विभागीय एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपे जाने का औचित्य क्या है।

कोरिया जिले का कार्यकाल भी फिर चर्चा में...

इस आदेश के बाद वर्तमान कलेक्टर का पूर्व कार्यकाल भी चर्चा में आ गया है, जानकारों का कहना है कि जब वे कोरिया जिले में कलेक्टर थीं, तब भी दो नियमित शासन नियुक्त जनपद पंचायत सीईओ जिला कार्यालय में कार्यरत रहे,जबकि जनपद पंचायतों में अन्य अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया था,यह भी दावा किया जा रहा है कि उस समय इस विषय को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन था तथा शासन नियुक्त अधिकारियों के संबंध में न्यायालय के निर्देशों की भी चर्चा हुई थी,हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि संबंधित न्यायालयीन अभिलेखों और शासन के रिकॉर्ड से ही हो सकती है, फिर भी वर्तमान आदेश के बाद उस पुराने प्रशासनिक निर्णय की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है।

शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण समाप्त करने के दावे

राज्य शासन ने पिछले कुछ समय में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए,संलग्न शिक्षकों को मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए, विद्यालयों में शिक्षक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए,शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने मूल दायित्वों का निर्वहन करें,इन्हीं निर्देशों के बाद प्रदेश के कई जिलों में संलग्नीकरण समाप्त करने की कार्रवाई भी हुई,ऐसे में बलरामपुर-रामानुजगंज का यह आदेश कई प्रशासनिक और नीतिगत प्रश्न खड़े कर रहा है।

क्या यह शासन की मंशा के अनुरूप है?

सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि यदि शासन का उद्देश्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को पुनः शिक्षा व्यवस्था में वापस लाना है, तो क्या मूलतः प्रधान पाठक रहे अधिकारी को जनपद पंचायत सीईओ का प्रभार देना उसी नीति के अनुरूप माना जाएगा? यदि यह केवल प्रशासनिक आवश्यकता है तो नियमित सीईओ की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? क्या जिले में योग्य प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं थे? क्या यह व्यवस्था केवल अस्थायी है या लंबे समय तक जारी रहेगी? इन प्रश्नों के उत्तर फिलहाल प्रशासन की ओर से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं।

क्या प्रशासनिक आवश्यकता बनी वजह?

प्रशासनिक विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि कई बार रिक्त पदों,अधिकारियों की कमी या प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त प्रभार देना शासन व्यवस्था का सामान्य हिस्सा होता है,यदि कुसमी जनपद पंचायत में नियमित सीईओ उपलब्ध नहीं थे, तो संभव है कि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों,इसलिए यह व्यवस्था की गई हो,हालांकि आदेश में इस प्रकार की परिस्थितियों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है।

कलेक्टर का नया आदेश बना चर्चा का विषय

प्रधान पाठक को सौंपा जनपद पंचायत CEO का प्रभार

शिक्षा विभाग के संलग्नीकरण समाप्त करने के सरकारी दावों के बीच जारी आदेश पर उठे सवाल

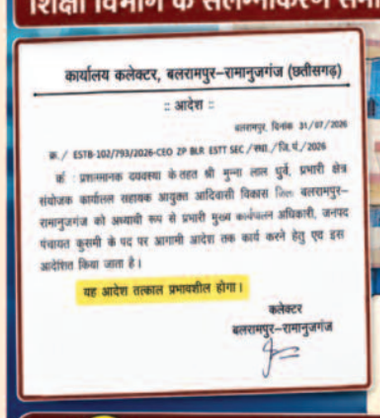
कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)
:: आदेश ::
बलरामपुर, दिनांक 31/07/2026
क्र./ ESTB-102/793/2026-CEO ZP BLR ESTT SEC /स्था./जि.पं./2026
कृ : प्रशासनिक व्यवस्था के तहत श्री मुन्ना लाल धुर्वे, प्रभारी क्षेत्र संयोजक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुसमी के पद पर आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु एवं इस आदेशित किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कलेक्टर
बलरामपुर-रामानुजगंज

- मूल पद प्रधान पाठक, फिर भी मिला जनपद CEO का प्रभार
- शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेशों के बीच नया आदेश
- क्या शासन की मंशा और जिला प्रशासन के निर्णय में है विरोधाभास?
- कोरिया जिले में भी कलेक्टर के कार्यकाल में उठे थे सवाल

? क्या प्रशासनिक आवश्यकता बनी वजह?

सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस...

आदेश सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं,एक पोस्ट में लिखा गया संलग्नीकरण समाप्त करने के दावों की खुली पोल, प्रधान पाठक को मिला सीईओ का प्रभार,यद्यपि यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि आदेश को लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है।

उठ रहे हैं कई अहम सवाल...

- क्या यह आदेश शासन की संलग्नीकरण समाप्त करने की नीति से मेल खाता है?
- क्या प्रधान पाठक का मूल विभाग अब भी शिक्षा विभाग ही माना जाएगा?
- क्या इस आदेश के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा शासन स्तर से कोई अनुमति ली गई?
- क्या भविष्य में ऐसे आदेशों पर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे?
- क्या अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू है?

क्या कहते हैं दस्तावेज?

- मूल पद – प्रधान पाठक।
- वर्ष 2024 में आदिम जाति विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति।
- वर्तमान में सहायक आयुक्त कार्यालय में प्रभारी क्षेत्र संयोजक।
- 31 जुलाई 2026 को कुसमी जनपद पंचायत के प्रभारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए।

मुख्य सवाल...

जब शासन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर लौटाने की नीति लागू कर रहा है, तब क्या मूलतः प्रधान पाठक रहे अधिकारी को जनपद पंचायत सीईओ का प्रभार देना उसी नीति की भावना के अनुरूप माना जाएगा,या यह केवल प्रशासनिक आवश्यकता के तहत लिया गया निर्णय है? इस प्रश्न का उत्तर अब जिला प्रशासन और राज्य शासन के स्पष्टीकरण से ही स्पष्ट हो सकेगा।

भालू के हमले में महिला गंभीर, खुखड़ी बीनने गई थी जंगल

मैनपाट के सरभंजा डुमरगोड़ा की घटना,सिर और कूल्हे को नोचा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मैनपाट क्षेत्र में जंगली भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला मंगलवार सुबह जंगल में खुखड़ी बीनने गई थी,तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मैनपाट के सरभंजा ग्राम पंचायत अंतर्गत डुमरगोड़ा निवासी कुंती माझी,पति शिवकुमार माझी मंगलवार सुबह करीब 6 बजे अन्य लोगों के साथ जंगल में खुखड़ी बीनने गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। भालू ले महिला के सिर व कूल्हे को नोच कर जख्मी कर दिया। साथ में खुखड़ी बीन रहे लोगों के चिल्लाने की आवज सूनकर भालू वहां से भाग गया। भालू द्वारा गंभीर रूप से जख्मी किए जाने से महिला बेहोश हो गई। साथ में खुखड़ी बीनने गए लोगों ने महिला के घर आकर घटना की जानकारी उसके परिजन को दी। परिजन जंगल से उसे घर लाए और एंबुलेंस से उसे कमलेश्वरपुर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।

कपड़ा दुकान में भीषण आग, 50 लाख से अधिक का नुकसान

-संवाददाता-

रामानुजगंज,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर के स्टेट बैंक रोड स्थित एक कपड़ा व्यवसायी की दुकान में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दुकान इसकी चपेट में आ गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अग्निकांड में 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5.30 बजे टहलने निकले लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तत्काल दुकान संचालक निहाल जायसवाल को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और दुकान में रखा कपड़ा व अन्य सामान जलने लगा था। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फायर ब्रिगेड वाहन का पानी समाप्त हो जाने से आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद नगर पालिका के पानी के टैंकर की मदद से स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने में सहयोग किया।

सब-इंजीनियर के सूने मकान से 20 लाख के जेवर-कैश पार

काशी दर्शन पर गए थे दंपती,लौटे तो टूटा मिला ताला;सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए चोर,डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम ने की जांच...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित कोणार्क रेसीडेंसी में चोरों ने एनएच विभाग में पदस्थ सब-इंजीनियर के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय सब-इंजीनियर पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बनारस गए थे। सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एनएच विभाग में पदस्थ सब-इंजीनियर रितेश सिंह का मकान कोणार्क रेसीडेंसी में है। 1 अगस्त को वे पत्नी के साथ बनारस गए थे। घर में उनकी मां और बच्चे मौजूद थे, लेकिन शनिवार शाम करीब 7 बजे वे भी पुराने घर नमनाकला चले गए। इसके बाद मकान पूरी तरह सूना हो गया। 3 अगस्त की रात जब रितेश सिंह पत्नी के साथ लौटे तो मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर मुख्य दरवाजे का सेंट्रल लॉक भी टूटा हुआ था। तीनों बेडरूम की आलमारियों के ताले टूटे मिले और उनमें रखे करीब 25 हजार रुपए नकद तथा 18 से 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर गायब थे। घटना देखकर दंपती ने तत्काल गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना दी।

डीवीआर भी साथ ले गए चोर : सूचना पर मंगलवार सुबह पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वायड ने कुछ स्थानों तक सुराग तलाशने का प्रयास किया, लेकिन बाद में दिशा भटक गई। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगर और फुट प्रिंट के नमूने जुटाए। प्रारंभिक जांच में एक बेडरूम की खिडक़ी की ग्रिल टूटी मिली है। आशंका है कि चोर इसी रास्ते से फरार हुए। मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन आरोपी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। अब पुलिस आसपास के मकानों और संभावित भागने के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

सरगुजा को मिले नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,रितेश चौधरी ने संभाला पदभार

जनसेवा,अपराध नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता,डीआईजी-एसएसपी से की सौजन्य भेंट

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग के आदेश के तहत राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारी रितेश चौधरी ने सरगुजा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने,अपराध नियंत्रण को मजबूत करने तथा आमजन को संवेदनशील एवं पारदर्शी पुलिस सेवा उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत एएसपी रितेश चौधरी ने डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) से सौजन्य भेंट की। इस दौरान जिले की कानून-व्यवस्था,अपराध नियंत्रण, जनसेवा, सामुदायिक पुलिसिंग तथा पुलिसिंग की प्राथमिकताओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्यप्रणाली का अवलोकन भी किया।

शाखाओं की समीक्षा, समयबद्ध कार्य के निर्देश : नवपदस्थ एएसपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों से परिचय प्राप्त करते हुए शाखावार कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर सभी कार्यों का समयबद्ध,गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालयीन कार्यों में गति लाने और आम नागरिकों को त्वरित एवं बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

सामुदायिक पुलिसिंग को मिलेगा बढ़ावा : रितेश चौधरी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के साथ-साथ अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण,संवेदनशील पुलिसिंग और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी बनाया जाएगा।

युवक को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक लाख की मांग,महिला पर केस दर्ज

पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया ब्लैकमेलिंग व उगाही के प्रयास का मामला,जांच शुरू

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर के बौरीपारा निवासी एक युवक को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रुपये की मांग करने के आरोप में पुलिस ने महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पीड़ित युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार बौरीपारा निवासी पुष्पा पटेल ने थाने में आवेदन देकर बताया कि वह गृहिणी हैं। उनके पुत्र वर्षित पटेल को असोला निवासी भारती दास ने मोबाइल फोन पर एक लाख रुपये देने की मांग की। आरोप है कि रुपये नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा देने की धमकी दी गई। शिकायत में कहा गया है कि वर्षित पटेल ने रकम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1 अगस्त 2026 को भारती दास ने उसके खिलाफ अंबिकापुर थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी,जिसके आधार पर उसे जेल भेज दिया गया। पुष्पा पटेल ने अपने आवेदन में पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने,मोबाइल कॉल,चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी की पावन माटी युक्त कलश लेकर सरगुजा पहुंचेगा 'समरसता संकल्प अभियान'

संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर भाजपा निकालेगी जिलेभर में कलश यात्रा,समरसता और सामाजिक सद्भाव का दिया जाएगा संदेश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र माटी युक्त कलश अब सरगुजा जिले में समरसता,समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश लेकर भ्रमण करेगी। यह अभियान गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आगामी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,संत समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पवित्र कलशों का पूजन किया गया। इसके बाद प्रदेश के सभी 36 संगठनात्मक जिलों के भाजपा जिलाध्यक्षों को कलश सौंपे गए तथा कलश यात्रा रथों को रवाना किया गया। भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जिला टोली के साथ पवित्र कलश लेकर अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कलश बुधवार को अंबिकापुर पहुंचेगा,जहां राम मंदिर में श्रद्धापूर्वक स्वागत एवं पूजन के बाद जिले के विभिन्न मंडलों में भ्रमण करेगा। जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक समानता, भाईचारे और मानवता की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने तथा संत रविदास के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। वाराणसी से आई पवित्र माटी युक्त कलश का जिलेभर में श्रद्धापूर्वक स्वागत किया जाएगा और इसके माध्यम से सामाजिक समरसता को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद हर्ष,मधुसूदन शुक्ला,संतोष दास,वैभव सिंह देव, आरडी चौहान,राधा रवि,आशीष गुप्ता,कमलेश तिवारी,मनोज कंसारी सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

CMYK

रामानुजनगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : सागौन तस्करी की कोशिश नाकाम,चार लट्ठों से लदा पिकअप जब्त,आरोपी फरार

मुखबिर की सूचना पर आधी रात जंगल में घेराबंदी...वन अमले ने दिखाई तत्परता...

वन संपदा की सुरक्षा के लिए रात्रिकालीन गश्त का असर, अवैध काष्ठ परिवहन करने वालों पर विभाग की सख्ती

-संवाददाता-
सूरजपुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध काष्ठ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन के लट्ठों से लदे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रात्रिकालीन गश्त के दौरान की गई,वन विभाग की सक्रियता के चलते अवैध काष्ठ परिवहन की कोशिश विफल हो गई, हालांकि मौके का फायदा उठाकर लकड़ी लोड कर रहे आरोपी अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार होने में सफल रहे। विभाग ने वाहन एवं जब्त वनोपज को सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हुए भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूचना मिलते ही हरकत में आया वन अमला

वन विभाग के अनुसार 2 अगस्त 2026 की रात मुखबिर से सूचना मिली कि रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से सागौन काष्ठ का परिवहन किया जा रहा है,सूचना की गंभीरता को देखते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी पूजा यादव ने तत्काल वनकर्मियों की टीम गठित कर क्षेत्र में सघन रात्रिकालीन गश्त के निर्देश दिए,टीम को संभावित मार्गों पर निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए भेजा गया।

तड़के तीन बजे जंगल की ओर जा रहे वाहन पर दी दबिश

वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही थी। इसी दौरान 3 अगस्त की सुबह लगभग तीन बजे परिसर छिंदिया क्षेत्र में एक पिकअप वाहन संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल की ओर जाता दिखाई दिया। वाहन की गतिविधि संदिग्ध लगने पर वनकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी की और दबिश दी। मौके पर वाहन क्रमांक सीजी-15 एसी-1294 में सागौन प्रजाति के चार नग लट्ठे लोड पाए गए, वनकर्मियों को देखकर वाहन में लकड़ी लोड कर रहे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। टीम ने उनका पीछा करने का प्रयास किया,लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके।

जब्त वाहन और वनोपज सुरक्षित अभिरक्षा में...

कार्रवाई के बाद जब्त पिकअप वाहन और सागौन काष्ठ को वन परिक्षेत्र कार्यालय रामानुजनगर लाकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है,विभाग अब फरार आरोपियों की पहचान करने तथा लकड़ी के स्रोत का पता लगाने में जुट गया है,साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि लकड़ी की कटाई किस स्थान से की गई और इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

वनकर्मियों की सतर्कता से मिली सफलता-इस पूरी कार्रवाई में वनरक्षक राहुल साहू, सुनील कुमार तथा बिजेश्वर सिंह ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही,वन विभाग ने टीम की तत्परता और सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर कार्रवाई के कारण बड़ी मात्रा में अवैध वनोपज का परिवहन रोका जा सका।

परिवहन के लिए नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज-वन विभाग द्वारा वाहन चालक से पूछताछ की गई,लेकिन वह सागौन काष्ठ के परिवहन से संबंधित कोई वैध अनुज्ञप्ति,परिवहन पास अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका,दस्तावेजों के अभाव में विभाग ने तत्काल वाहन सहित काष्ठ को जब्त कर लिया, वन अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला अवैध वनोपज परिवहन का प्रतीत होने पर भारतीय वन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है।

वन विभाग ने दी कड़ी चेतावनी-वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि रामानुजनगर वन परिक्षेत्र सहित जिले के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध कटाई और वनोपज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए रात्रिकालीन गश्त और निगरानी लगातार जारी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वन संरक्षण के लिए जनसहयोग की अपील

वन विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी अवैध कटाई,लकड़ी का भंडारण अथवा अवैध परिवहन की जानकारी मिले तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें, विभाग का कहना है कि जनसहयोग से ही वन संपदा की प्रभावी सुरक्षा संभव है और जंगलों को अवैध दोहन से बचाया जा सकता है,वन विभाग का मानना है कि इस प्रकार की सतत कार्रवाई न केवल वन तस्करों पर अंकुश लगाएगी,बल्कि जिले में वन संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक संदेश देगी।

WE क्लब अम्बिकापुर ग्रेटर स्टार की नई टीम ने संभाली कमान

ज्योति चोपड़ा अध्यक्ष,सपना चोपड़ा सचिव और बर्खा चोपड़ा कोषाध्यक्ष बनीं,सेवा,समर्पण और महिला सशक्तिकरण का लिया संकल्प

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

WE क्लब अम्बिकापुर ग्रेटर स्टार का शपथ ग्रहण एवं पदभार ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में नई कार्यकारिणी ने समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वंदना दत्ता थीं। शपथ अधिकारी के रूप में आशा राणा,फाउंडर मेंबर अमरजीत कथूर तथा एरिया एडवाइजर स्नेहा प्रभा त्रिपाठी मंचासीन रहीं। वहीं इति चतुर्वेदी,मुक्ता गुप्ता सहित क्लब की सभी सदस्याओं की उपस्थिति ने समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं WE प्रार्थना के साथ हुआ। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ज्योति चोपड़ा ने अध्यक्ष,सपना चोपड़ा ने सचिव तथा बर्खा चोपड़ा ने कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हुए संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप पारदर्शिता,सेवा और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि WE क्लब महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के साथ शिक्षा,स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगा। उन्होंने नई टीम से संगठन की गरिमा बनाए रखते हुए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। समारोह के दौरान अतिथियों का स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। सभी सदस्याओं ने नवकार्यकारिणी का स्वागत करते हुए क्लब की आगामी सामाजिक एवं सेवा गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का भरोसा दिलाया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए इस कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं सदस्याओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा नई कार्यकारिणी के सफल एवं जनसेवा से परिपूर्ण कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गईं।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार,पीड़िता की परिजन ने थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अगस्त 2026 की देर रात ग्राम खलिबा निवासी सुरेन्द्र चेरवा उनकी नाबालिग बेटी को पसंद करने और शादी करने का झांसा देकर मोटर साइकिल से अपने साथ ले गया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन नाबालिग को आरोपी के घर से वापस लेकर आए। प्रार्थिया की शिकायत पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 497/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने सुरेन्द्र चेरवा (20 वर्ष), पिता सुखलाल चेरवा,निवासी ग्राम खलिबा,थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय,सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, आरक्षक कुंदन पाण्डेय, भीम सिंह,उमेश गुप्ता एवं दीपक सोनवानी की सक्रिय भूमिका रही।

केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी में तीन तस्कर गिरफ्तार : हाथी के तीन जबड़े बरामद

सीमावर्ती वन परिक्षेत्र की निगरानी और पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल...

-संवाददाता-
रामानुजगंज,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के संवेदनशील रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और राज्य उड़नदस्ता दल की संयुक्त कार्रवाई ने अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी के एक कथित नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई में हाथी के जबड़ों की कथित तस्करी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के साथ ही स्थानीय वन विभाग की कार्यप्रणाली, निगरानी व्यवस्था और सूचना तंत्र पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वन विभाग के अनुसार, 3 अगस्त 2026 को रामानुजगंज स्थित आमंत्रण धर्मशाला के कमरा क्रमांक-205 में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान एक बैग से हाथी के तीन जबड़े बरामद किए गए। मौके से तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के पलामू जिले के संतोष कुमार विश्वकर्मा (42 वर्ष),रामानुजगंज निवासी अजय कुमार गुप्ता (49 वर्ष) तथा सतेन्द्र कुमार रजक (50 वर्ष) शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48(क), 50, 51 एवं 52 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रामानुजगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सबसे बड़ा सवाल—जब नेटवर्क सक्रिय था तो स्थानीय वन अमला क्या कर रहा था? कार्रवाई जितनी बड़ी है,उससे कहीं अधिक चर्चा इस बात की है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क की भनक स्थानीय वन विभाग को क्यों नहीं लगी। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में यदि अंतरराज्यीय तस्करी का नेटवर्क सक्रिय था तो यह गतिविधियां एक-दो दिन में विकसित नहीं हुई होंगी।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब केंद्रीय एजेंसी और राज्य उड़नदस्ता दल को कार्रवाई करनी पड़ी,तब स्थानीय वन अमले की भूमिका क्या रही? क्या नियमित गश्त,खुफिया सूचना संग्रह और निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई थी? यदि स्थानीय स्तर पर सतर्कता प्रभावी होती तो क्या इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत आती?

पौधारोपण की तस्वीरें ज्यादा, वन्यजीव संरक्षण कम? स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग की प्राथमिकता पौधारोपण अभियान, फोटो सेशन और प्रचार गतिविधियां अधिक दिखाई देती हैं, जबकि वन्यजीव संरक्षण और तस्करी रोकने जैसे मूल दायित्वों पर अपेक्षित गंभीरता नजर नहीं आती। लोगों का मानना है कि यदि सीमा क्षेत्रों में नियमित निगरानी,मुखबिर तंत्र और संयुक्त अभियान प्रभावी रहते तो हाथी के अंगों की कथित तस्करी जैसा मामला सामने आने से पहले ही पकड़ा जा सकता था।

'मीडिया मैनेजमेंट' के नाम पर सौदेबाजी की भी चर्चा : कार्रवाई के बाद रामानुजगंज शहर में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि मामले को दबाने और 'मीडिया मैनेजमेंट' के नाम पर कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर सौदेबाजी की कोशिश की जा रही थी। चर्चा है कि इसके लिए लगभग 5 लाख रुपये तक की डील की बात चल रही थी। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए इन चर्चाओं को फिलहाल केवल स्थानीय स्तर पर प्रचलित दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि इस संबंध में कोई शिकायत या साक्ष्य सामने आते हैं तो उनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक होगी।

अब नजर जांच की दिशा पर : वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की इस कार्रवाई ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि वन्यजीव तस्करी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं,लेकिन साथ ही इसने स्थानीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहती है या फिर इस पूरे नेटवर्क, संभावित सहयोगियों तथा स्थानीय स्तर पर हुई किसी भी चूक की भी निष्पक्ष जांच की जाती है। इससे ही यह तय होगा कि यह कार्रवाई केवल एक गिरफ्तारी बनकर रह जाएगी या वन्यजीव तस्करी के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार साबित होगी।

पारदर्शिता पर भी उठ रहे सवाल

कार्रवाई के बाद वन विभाग की सूचना प्रणाली भी चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय पत्रकारों का आरोप है कि महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की जानकारी चुनिंदा माध्यमों तक ही सीमित रखी जाती है। कई बार केवल संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है,जबकि विस्तृत जानकारी मांगने पर जांच का हवाला देकर जवाब टाल दिया जाता है। पत्रकारों का कहना है कि कई मामलों में अधिकारियों से बाद में संपर्क भी नहीं हो पाता, जिससे कार्रवाई की वास्तविक स्थिति और तथ्यों की पुष्टि करना कठिन हो जाता है। इससे विभाग की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जवाबदेही तय करने की मांग तेज

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस कठोरता से तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसी प्रकार यह भी जांच होनी चाहिए कि कहीं स्थानीय स्तर पर निगरानी में लापरवाही या सूचना तंत्र की विफलता तो नहीं रही। उनका कहना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तो सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्यजीव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना मुश्किल होगा।

'सुरक्षित कैंपस' की पहल : छात्र-छात्राओं ने संभाली जागरूकता की कमान

राजीव गांधी पीजी कॉलेज में पॉश एक्ट और यौन उत्पीड़न रोकथाम पर अभियान,सर्वे के जरिए सुरक्षा सुधार के सुझाव भी दिए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर में छात्र-छात्राओं ने सुरक्षित एवं जागरूक परिसर के निर्माण की दिशा में पहल करते हुए पॉश एक्ट, यौन उत्पीड़न रोकथाम और विशाखा समिति की भूमिका पर जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सोशल इनोवेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट सेल, विशाखा समिति तथा मुहिम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महाविद्यालय के पांच विद्यार्थियों अंकिता,प्रीति,भूमिका,आशुतोष और अंबिके ने किया। उन्होंने छात्राओं के बीच किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए परिसर के उन स्थानों की जानकारी साझा की,जहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी (क्विज़) एवं अन्य संवादात्मक गतिविधियों के माध्यम से पॉश एक्ट और यौन उत्पीड़न से जुड़े अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी। कार्यशाला में लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया,जिनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़ने की जरूरत : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा इतने महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर नेतृत्व करना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित कर अपने व्यक्तित्व का भी समग्र विकास करना चाहिए।

विशेषज्ञों ने बताए अधिकार और कानूनी प्रावधान : कार्यक्रम में विशाखा समिति की संयोजक डॉ. संगीता पाण्डेय तथा सोशल इनोवेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट सेल के संयोजक डॉ. दीपक सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। वहीं विधि विभाग की डॉ. पूनम ने तकनीकी सत्र के दौरान पॉश एक्ट, यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी अधिकारों तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में डॉ. कामिनी ने आभार व्यक्त किया।

सहयोगी संस्थाओं की रही सक्रिय भागीदारी : इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एस.एन. पाण्डेय, आईक्यूएसी संयोजक डॉ. उमेश कुमार पांडेय, डॉ. माधवेन्द्र तिवारी, डॉ. रजनी सारथी तथा डॉ. अनुजा कुजूर उपस्थित रहीं। वहीं मुहिम फाउंडेशन की ओर से आकृति, रोस और ऋषिकेश ने भी कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। उल्लेखनीय है कि यह अभियान चलाने वाले पांचों विद्यार्थी राजीव गांधी पीजी कॉलेज एवं मुहिम फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 'यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी एक्शन' प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रतिभागी हैं। विद्यार्थियों की यह पहल महाविद्यालय परिसर को अधिक सुरक्षित, समावेशी और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास मानी जा रही है।

गुरुधासीदास टाइगर रिजर्व में करोड़ों के स्टॉप डैम और तालाबों में नहीं ठहरा पानी

बरसात में सूखता विकास!

- मूसलाधार बारिश के बाद भी कई स्टॉप डैम में नहीं जमा मानक स्तर तक पानी
- कागजों में जल संरक्षण के दावे, धरातल पर सूखी संरचनाएं; उठे सवाल

मेंड्रा बैरियर से आगे गिधरे मार्ग का स्टॉप डैम

मेंड्रा बैरियर से आगे – चंदहा मार्ग

गिधरे मार्ग का तालाब : पानी दीवार तक नहीं पहुंचा

तालाब की मिट्टी की दीवार में बड़ी दरार

वन्यजीवों पर खतरा

जलस्रोत नहीं होंगे तो गर्मी में वन्यजीव आएंगे आबादी की ओर, संघर्ष की बढ़ेगी आशंका

तकनीकी सवाल
- क्या सही स्थल चयन और वैज्ञानिक सर्वे हुआ?
- क्या निर्माण योग्य इंजीनियर की देखरेख में हुआ?
- क्या डिजाइन और ढाल में है कमी?
- क्या गुणवत्ता मानकों का हुआ पालन?
- जांच रिपोर्ट क्यों नहीं हुई सार्वजनिक?

जनता की मांग
स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट हो, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो, दोषियों पर हो कार्रवाई

करोड़ों खर्च,फिर भी प्यासे जलस्रोत! गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की जल संरचनाओं पर उठे सवाल

वन्यजीवों के लिए बने जलस्रोत खुद प्यासे! करोड़ों की परियोजनाओं की होगी जांच?

स्टॉप डैम बने,पानी नहीं रुका! गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में करोड़ों की परियोजनाओं पर सवाल

जंगल में जल संरक्षण या सरकारी धन की बर्बादी? बारिश के बाद भी सूखे पड़े स्टॉप डैम

बारिश बेअसर,करोड़ों की जल संरचनाएं बेकार! टाइगर रिजर्व में निर्माण गुणवत्ता पर घिरे सवाल

करोड़ों की लागत, अधूरा जल संरक्षण! वन्यजीवों के लिए बने जलस्रोतों की खुली पोल

फॉलोअप ग्राउंड रिपोर्ट : बरसात में भी नहीं भरे स्टॉप डैम, अब तकनीकी ऑडिट की मांग तेज

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

प्रकृति के संरक्षण और वन्यजीवों के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में बनाए गए स्टॉप डैम और तालाब अब स्वयं सवालों के घेरे में हैं,करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित इन कृत्रिम जल संरचनाओं का उद्देश्य गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए स्थायी जल स्रोत तैयार करना था, लेकिन इस वर्ष लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बावजूद कई संरचनाओं में अपेक्षित जलभराव नहीं हो पाया, इसके विपरीत प्राकृतिक नाले,छोटे गड्ढे और जलधाराएं पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं,जबकि कृत्रिम संरचनाएं अपनी क्षमता के अनुरूप पानी रोकने में असफल नजर आ रही हैं,यह स्थिति केवल निर्माण गुणवत्ता का ही प्रश्न नहीं उठाती,बल्कि करोड़ों रुपये की लागत से संचालित जल संरक्षण योजनाओं की उपयोगिता और वन्यजीव संरक्षण की रणनीति पर भी गंभीर बहस खड़ी करती है।

मानसून ने खोली विकास के दावों की हकीकत

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्टॉप डैमों और तालाबों का निर्माण पूरे वर्ष वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था,वे वर्षा ऋतु में ही पर्याप्त जल संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में जब बारिश के चरम समय में पानी नहीं रुक रहा, तो गर्मी के मौसम में इन संरचनाओं से क्या उम्मीद की जा सकती है, विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी स्टॉप डैम या तालाब की सफलता केवल उसकी दीवार की ऊंचाई से नहीं, बल्कि कैचमेंट एरिया,जल प्रवाह,भूमि की ढाल,मिट्टी की प्रकृति, जल निकासी व्यवस्था और वैज्ञानिक डिजाइन पर निर्भर करती है,यदि इन पहलुओं की अनदेखी की जाए तो भारी वर्षा भी जल संरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती।

ग्राउंड रिपोर्ट : मेण्ड्रा-गिधरे मार्ग पर सवालों के घेरे में स्टॉप डैम

मेण्ड्रा बैरियर से आगे गिधरे मार्ग पर निर्मित लगभग सात फीट ऊंची और करीब 50 फीट लंबी कंक्रीट संरचना का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सभी गेट बंद होने के बावजूद जलस्तर सीमित था,पानी केवल एक हिस्से में जमा दिखाई दिया,जबकि पूरी संरचना में पर्याप्त जलभराव नहीं था,स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी लागत और आकार वाली संरचना से अपेक्षा थी कि यह लंबे समय तक बड़ी मात्रा में पानी संग्रहित करेगी, जिससे वन्यजीवों को गर्मी में राहत मिल सके।

तालाब में दरार,डिजाइन और निर्माण पर उठे सवाल-गिधरे मार्ग पर बने एक तालाब की स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई दी, स्थल निरीक्षण के दौरान देखा गया कि तालाब का गड्ढा अपेक्षाकृत छोटा है,जबकि उसके चारों ओर ऊंची मिट्टी की पाल बनाई गई है, पानी पाल तक पहुंच ही नहीं पाया,ग्रामीणों के अनुसार तालाब का प्राकृतिक ढाल भी सही दिशा में नहीं दिखाई देता, निरीक्षण के दौरान मिट्टी की दीवार में बड़ी दरार (क्रैक) भी दिखाई देने का दावा किया गया, यदि यह स्थिति सही है,तो लगातार वर्षा की स्थिति में संरचना की मजबूती पर भी प्रश्न उठते हैं,हालांकि इसकी वास्तविक तकनीकी स्थिति का आकलन विशेषज्ञों की जांच के बाद ही संभव होगा।

चंदहा मार्ग: दीवार है,लेकिन पानी नहीं-मेण्ड्रा बैरियर से आगे चंदहा मार्ग पर बने स्टॉप डैम की स्थिति भी सवालों के घेरे में है,दूर से देखने पर केवल कंक्रीट की दीवार और खोदा गया क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन पर्याप्त जलभराव नहीं दिखा, स्थानीय ग्रामीण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यहां यदि किसी चीज की सबसे अधिक कमी दिखाई देती है तो वह पानी है।

वन्यजीवों पर पड़ सकता है सीधा असर-गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व देश के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में से एक है,जहां हाथी, भालू,तेंदुआ,हिरण,जंगली सूअर सहित अनेक वन्यजीव निवास करते हैं,यदि कृत्रिम जल स्रोत पर्याप्त पानी नहीं रोक पाए तो गर्मी के दिनों में वन्यजीवों को पानी की तलाश में जंगल छोड़कर आबादी की ओर आना पड़ सकता है, वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट बढ़ने पर मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है, जिसका असर वन्यजीवों और ग्रामीणों दोनों पर पड़ेगा।

कई तकनीकी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित

यह पूरा मामला कई गंभीर तकनीकी सवाल खड़े करता है क्या निर्माण से पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया गया था? क्या कैचमेंट एरिया का सही आकलन किया गया? क्या योग्य सिविल एवं हाइड्रोलिक इंजीनियरों की निगरानी में निर्माण हुआ? क्या डिजाइन और निर्माण मानकों का पालन किया गया? यदि भारी बारिश के बाद भी पानी नहीं रुक रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

जन सहयोग समिति ने की तकनीकी ऑडिट की मांग...

कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जल संरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच आवश्यक है, उन्होंने कहा कि समिति इस मामले की शिकायत वन मुख्यालय रायपुर, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तक पहुंचाएगी, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें...

स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने मांग की है कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में बने सभी स्टॉप डैम एवं तालाबों का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया जाए, निर्माण की गुणवत्ता और लागत की जांच कराई जाए, जल संरक्षण क्षमता का वैज्ञानिक मूल्यांकन कराया जाए, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, यदि अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

क्या तय होगी जवाबदेही?

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपये की लागत से बनी जल संरचनाओं की वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि केवल निर्माण कार्य पूरा कर देना पर्याप्त नहीं है, यदि संरचनाएं अपने मूल उद्देश्य–जल संरक्षण–को ही पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो सार्वजनिक धन के उपयोग और वन्यजीव संरक्षण की पूरी योजना पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संबंधित विभाग इन सवालों का तकनीकी और तथ्यात्मक जवाब देगा, या फिर यह मामला भी फाइलों तक सीमित रह जाएगा? क्योंकि यह केवल निर्माण कार्य का मामला नहीं, बल्कि जंगल के बेजुबान वन्यजीवों के भविष्य और करोड़ों रुपये की सार्वजनिक राशि की जवाबदेही का भी प्रश्न है।

नगर पंचायत पटना में करों का मुद्दा गरमाया...जल,मकान,दुकान और व्यावसायिक कर में 50 प्रतिशत तक कमी की मांग, नागरिकों ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

नगर पंचायत बनने के बाद बढ़ा करों का बोझ,गरीब,किसान और मजदूर परिवारों को राहत देने की मांग...

-संवाददाता-

पटना/कोरिया,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर पंचायत पटना में जल कर,मकान कर, दुकान कर,व्यावसायिक कर एवं समेकित कर की दरों को लेकर लोगों में असंतोष सामने आने लगा है, नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपकर वर्तमान करों में 50 प्रतिशत तक कमी करने की मांग की है, आवेदन में तर्क दिया गया है कि नगर पंचायत बनने के बाद करों में हुई वृद्धि का सीधा असर गरीब,किसान और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है,जिससे उनके लिए आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।

नगर पंचायत बनने के बाद बदली व्यवस्था, बढ़ा करों का बोझ?-आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पटना को नगर पंचायत का दर्जा मिले लगभग दो वर्ष हो चुके हैं,इससे पहले यहां ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू थी,जहां करों का स्वरूप और दरें अलग थीं,नगर पंचायत बनने के बाद विभिन्न प्रकार के कर निर्धारित किए गए, जिन्हें लेकर अब स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है,आवेदन के अनुसार क्षेत्र की अधिकांश आबादी किसान,मजदूर और निम्न आय वर्ग से जुड़ी है,ऐसे में वर्तमान कर दरें आम नागरिकों की आर्थिक क्षमता के अनुरूप नहीं हैं।

चार प्रमुख करों में राहत की मांग-नगरवासियों ने अपने आवेदन में निम्नलिखित करों में 50 प्रतिशत तक कमी की मांग की है जल कर,मकान कर,दुकान/व्यावसायिक कर, समेकित कर,आवेदन में कहा गया है कि वर्तमान कर निर्धारण 'अधिक' है और आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है,इसलिए नगर पंचायत परिषद जनहित को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा कर राहत प्रदान करे।

हस्ताक्षर कर नागरिकों ने जताई एकजुटता-आवेदन पर कई नागरिकों के हस्ताक्षर दर्ज हैं तथा नगर पंचायत कार्यालय की प्राप्ति मुहर भी दिखाई दे रही है,इससे स्पष्ट होता है कि यह मांग व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से रखी गई है,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि करों में कमी की जाती है तो आम नागरिकों को राहत मिलेगी और नगर पंचायत के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

अब परिषद और प्रशासन के निर्णय पर निगाह-ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब यह देखना होगा कि नगर पंचायत प्रशासन और निर्वाचित परिषद इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं, यदि करों की समीक्षा की जाती है तो हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकता है, वहीं यदि वर्तमान दरें यथावत रहती हैं तो नागरिकों की ओर से आगे भी आंदोलन या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव बनाया जा सकता है।

प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण

इस विषय पर नगर पंचायत प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा,संभव है कि कर निर्धारण शासन के नियमों, अधिनियमों अथवा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर किया गया हो, ऐसे में प्रशासन का स्पष्टीकरण सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

नगरवासियों की प्रमुख मांगें...

- जल कर में 50% तक कमी।
- मकान कर में 50% तक कमी।
- दुकान एवं व्यावसायिक कर में 50% तक कमी।
- समेकित कर की दरों की पुनर्समीक्षा।
- गरीब,किसान एवं मजदूर परिवारों को राहत।

C M Y K

बैकुंठपुर-शिवपुर चरचा में चुनावी बिगुल..जनता लिखेगी सत्ता की नई पटकथा

चार महीने बाद होगा राजनीतिक इम्तिहान,बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा में किसकी होगी जीत?

कोरिया की दो नगरपालिकाओं में दिलचस्प मुकाबला,इतिहास दोहराएगा या बनेगा नया अध्याय?

सत्ता भाजपा की...लेकिन क्या नगर पालिकाओं में भी बजेगा जीत का डंका?

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा में चुनावी बिसात तैयार,किसकी चाल पड़ेगी भारी?

गुटबाजी,टिकट और विकास...इन्हीं तीन सवालों पर टिकी कोरिया की चुनावी जंग

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा में चुनावी रण, क्या सत्ता का साथ मिलेगा या जनता बदलेगी समीकरण?

चार महीने बाद बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा में लोकतंत्र का महायुद्ध,जनता के मुद्दे बनेंगे हथियार या फिर गुटबाजी ही लिखेगी चुनावी पटकथा?

रवि सिंह

कोरिया/बैकुण्ठपुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। राजनीति में एक कहावत अक्सर सुनने को मिलती है,'चुनाव जनता लड़ती है,लेकिन हार अक्सर नेता आपस में लड़कर जाते हैं,'कोरिया जिले की दो प्रमुख नगरीय निकायों में बैकुंठपुर नगर पालिका और शिवपुर-चरचा नगर पालिका–का चुनावी इतिहास इस कहावत को कई बार सच साबित करता नजर आता है। वर्ष 2027 की शुरुआत में इन दोनों निकायों में चुनाव होने हैं,अभी लगभग चार महीने का समय शेष है,लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, दावेदार सक्रिय हैं,समर्थक अपने-अपने नेताओं के लिए माहौल बनाने में जुट गए हैं और दोनों प्रमुख दल–भाजपा और कांग्रेस–अपने चुनावी गणित को साधने में लगे हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव केवल नगर पालिका जीतने का नहीं, बल्कि सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा भी होगा,वहीं कांग्रेस इसे खोया जनाधार वापस पाने का अवसर मान रही है,लेकिन कोरिया की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां सत्ता की हवा हमेशा वोटों में नहीं बदलती,कई बार स्थानीय नाराजगी,उम्मीदवार की छवि और दलों की अंदरूनी राजनीति चुनाव का पूरा गणित बदल देती है।

बैकुंठपुर एवं शिवपुर-चरचा : नगर पंचायत से नगर पालिका बनने के बाद का चुनावी इतिहास

कोरिया जिले की बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा ऐसी नगरीय निकाय हैं, जिन्हें नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय राजनीति का केंद्र माना जाने लगा, नगर पालिका बनने के बाद से दोनों निकायों का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है और समय-समय पर मतदाताओं ने अलग-अलग राजनीतिक संदेश दिए हैं, नगर पालिका बनने के बाद बैकुंठपुर के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय तीरथ प्रसाद गुप्ता बने, स्थानीय स्तर पर उन्हें बैकुंठपुर को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिलाने का श्रेय भी दिया जाता है, वहीं शिवपुर-चरचा नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष राजेश सिंह निर्वाचित हुए, उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दोनों निकायों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, दूसरे चुनाव में भी प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास ही रही, लेकिन चुनावी नतीजों ने अलग तस्वीर पेश की, शिवपुर-चरचा में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में सफल रही, जबकि बैकुंठपुर में भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय तीरथ प्रसाद गुप्ता को निर्दलीय प्रत्याशी शैलेश शिवहरे ने पराजित कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए, तीसरे चुनाव में भी प्रदेश में भाजपा सरकार थी, इस बार शिवपुर-चरचा में अजीत लकड़ा ने जीत हासिल की, जबकि बैकुंठपुर में अशोक जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष बने। यानी दोनों निकायों में सत्ता का समीकरण फिर बदल गया और मतदाताओं ने नए नेतृत्व पर भरोसा जताया, चौथे चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दोनों नगरपालिकाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपनी मजबूत वापसी की। हालांकि, इसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं रहीं, बैकुंठपुर में आपसी अंतर्कलह और राजनीतिक खींचतान के कारण कांग्रेस को अपेक्षाकृत जल्द ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जबकि शिवपुर-चरचा में भी लगभग दो वर्ष बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए और कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ गई, नगर पालिका बनने के बाद के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा की जनता ने किसी एक दल को स्थायी जनादेश नहीं दिया है, यहां चुनावी परिणामों पर प्रदेश की सत्ता के साथ-साथ स्थानीय नेतृत्व, संगठनात्मक मजबूती, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और दलों की आंतरिक एकजुटता का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

बैकुंठपुर:जहां विरोधियों से ज्यादा अपनों ने नुकसान पहुंचाया-बैकुंठपुर नगर पालिका का पिछला चुनाव आज भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहता है,उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी,सामान्य धारणा थी कि सत्ता का लाभ कांग्रेस को मिलेगा,लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में गया,राजनीतिक विश्लेषणों में उस चुनाव का सबसे चर्चित निष्कर्ष यही रहा कि कांग्रेस को जितना नुकसान भाजपा ने नहीं पहुंचाया,उससे अधिक नुकसान उसकी अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी ने पहुंचाया, चुनाव जीतने के बाद भी यदि संगठन एकजुट न रहे तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है–बैकुंठपुर इसका उदाहरण माना जाता है,आज भी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा सुनाई देती है कि यदि कांग्रेस उस समय पूरी तरह एकजुट होती,तो परिणाम अलग भी हो सकते थे। हालांकि यह विश्लेषण राजनीतिक पर्यवेक्षकों की राय है और चुनावी परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं।

शिवपुर-चरचा: यहां मतदाता किसी का स्थायी वोट बैंक नहीं-शिवपुर-चरचा नगर पालिका की राजनीति को समझना आसान नहीं है, यहां के मतदाता समय-समय पर दोनों प्रमुख दलों को अवसर देते रहे हैं, अब तक के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो भाजपा और कांग्रेस–दोनों ने दो-दो बार नगर पालिका की सत्ता संभाली है, यानी यहां जनता ने किसी एक दल को स्थायी अधिकार नहीं दिया, यह भी सच है कि कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल के दौरान राजनीतिक समीकरण बदले और भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की, इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि स्थानीय राजनीति में केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं होता, संगठन और जनविश्वास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल-उम्मीदवार कौन?-

चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आएंगे, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न उम्मीदवार चयन का होगा, क्या पार्टी ऐसा चेहरा सामने लाएगी जिसे संगठन के सभी गुट स्वीकार करें? क्या टिकट वितरण के बाद असंतोष नहीं पनपेगा? क्या जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, वे पूरे मन से अधिकृत उम्मीदवार के लिए काम करेंगे? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, यदि कांग्रेस संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने में सफल रहती है तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है, लेकिन यदि पुराने मतभेद फिर सामने आए, तो विपक्ष को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती।

भाजपा के सामने भी आसान नहीं है रास्ता-

प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाता विधानसभा या लोकसभा से अलग सोच रखता है, यहां चर्चा मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय नेतृत्व की कम और नगर की सड़कों, सफाई व्यवस्था, पेयजल, नालियों, स्ट्रीट लाइट और स्थानीय विकास कार्यों की अधिक होती है, यदि जनता को लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है तो सत्ता विरोधी रुझान कमजोर पड़ सकता है। लेकिन यदि नगर की समस्याएं जस की तस रहीं, तो सत्ता पक्ष को भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे पहले टिकट का रण,फिर चुनाव का रण-राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों में असली मुकाबला मतदान वाले दिन नहीं,बल्कि टिकट घोषित होने के दिन शुरू हो जाता है,एक टिकट के लिए कई दावेदार होते हैं,टिकट मिलने पर उत्सव और टिकट कटने पर असंतोष–यह हर चुनाव की कहानी है, यदि कोई दल अपने असंतुष्ट नेताओं को समय रहते साथ नहीं रख पाया तो वही नेता चुनावी गणित बिगाड़ने का कारण भी बन सकते हैं।

जनता अब केवल वादे नहीं,हिसाब भी मांगेगी-इस बार मतदाता विकास का रिपोर्ट कार्ड भी देखेगा,नगर की सड़कें कैसी हैं? सफाई व्यवस्था में कितना सुधार हुआ? पेयजल की स्थिति क्या है? नगर पालिका की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं? जनप्रतिनिधि जनता के बीच कितने सक्रिय रहे? इन सवालों के जवाब चुनावी सभाओं से नहीं,बल्कि जनता के अनुभव से तय होंगे।

निर्दलीय उम्मीदवार भी बदल सकते हैं खेल-स्थानीय निकाय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, कई बार नाराज नेता निर्दलीय मैदान में उतरकर जीत-हार का अंतर तय कर देते हैं,इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों की कोशिश रहेगी कि टिकट वितरण के बाद असंतोष को कम से कम रखा जाए।

सियासत की असली परीक्षा अब शुरू-अगले चार महीने दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे,भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी,कांग्रेस स्थानीय मुद्दों,नगर पालिकाओं के कामकाज और सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी,लेकिन इन सबके बीच अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होगा।

व्यंग्य की नजर से...

चुनाव आते ही कई नेता अचानक हर गली,हर मोहल्ले और हर चौपाल के पुराने परिचित बन जाते हैं, जिन रास्तों पर वर्षों तक उनकी गाड़ियां नहीं गुजरीं, वहां भी धूल उड़ने लगती है,जिन नागरिकों का फोन महीनों तक नहीं उठता,वे चुनावी मौसम में 'सबसे सम्मानित मतदाता' बन जाते हैं,नगर की टूटी सड़कें चुनावी भाषणों में 'विकास की योजना' बन जाती हैं,नालियां 'प्रस्तावित कार्य' कहलाने लगती हैं और अधूरे वादे फिर से नए संकल्पों के साथ मंच पर लौट आते हैं,लेकिन कोरिया का मतदाता अब पहले जैसा नहीं माना जाता, पिछले चुनावों में उसने कई बार यह दिखाया है कि वह केवल नारों पर नहीं,परिस्थितियों और अपने अनुभवों के आधार पर भी फैसला ले सकता है।

अब निगाहें चार महीनों पर...

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा की चुनावी बिसात सज चुकी है,मोहरे अपनी-अपनी जगह लेने लगे हैं,रणनीतियां बन रही हैं, दावेदार सक्रिय हैं,राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है,अब देखना यह होगा कि इस बार जीत का रास्ता सत्ता की ताकत से निकलेगा,संगठन की मजबूती से, उम्मीदवार की लोकप्रियता से या फिर एक बार फिर किसी दल की अंदरूनी खींचतान पूरी बाजी पलट देगी,कोरिया की राजनीति का इतिहास एक बात जरूर कहता है...यहां चुनाव केवल मतों से नहीं,बल्कि भरोसे, संगठन और समय पर चली गई सही राजनीतिक चाल से जीते जाते हैं। अब जनता किसे अपना भरोसा सौंपेगी,इसका फैसला आने वाले चुनाव में होगा।

चरचा क्षेत्र में एचएमएस का बढ़ा कुनबा, बीएमएस के जेसीसी सचिव सुशील शर्मा ने साथियों संग थामा कोयला मजदूर सभा का दामन

नाथूलाल पांडेय के नेतृत्व और कामगार हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर एचएमएस में शामिल हुए श्रमिक नेता,संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प

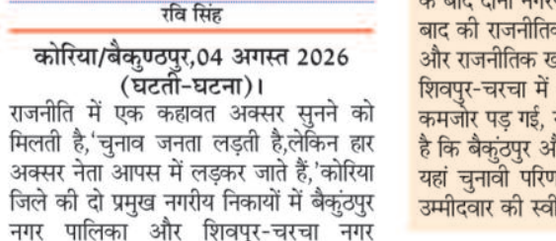

-संवाददाता-

बैकुंठपुर/चरचा,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। चरचा आरओ बैकुंठपुर क्षेत्र में कोयला मजदूर सभा (बीएमएस) को उस समय बड़ी मजबूती मिली,जब बीकेकेएमएस (बीएमएस) संगठन के चरचा ईस्ट ब्लॉक के जेसीसी एवं सचिव सुशील शर्मा ने अपने साथियों के साथ कोयला मजदूर सभा (एचएमएस) की सदस्यता ग्रहण की। संगठन में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का एचएमएस के पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। प्रवेश कार्यक्रम के दौरान कोयला मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता नाथूलाल पांडेय के नेतृत्व तथा संगठन की कामगार हितैषी नीतियों और सिद्धांतों पर विश्वास व्यक्त करते हुए नए सदस्यों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा श्रमिकों के हितों की आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया, कार्यक्रम में बैकुंठपुर क्षेत्र के अध्यक्ष हरी यादव एवं महामंत्री योगेंद्र मिश्रा ने संगठन में शामिल हुए सभी साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एचएमएस सदैव श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहा है तथा भविष्य में भी यह संघर्ष जारी रहेगा,इस अवसर पर यशपाल सिंह, अशोक निर्मलकर,महेश यादव,ज्ञानेंद्र पांडेय,अरविंद मिश्रा, आदित्य प्रताप सिंह, दशरथ मिश्रा,विनोद कुमार शुक्ल सहित बड़ी संख्या में एचएमएस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, कार्यक्रम का समापन 'सम्मान, संगठन और कामगार हित' के संकल्प के साथ हुआ, उपस्थित सदस्यों ने एकजुट होकर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा संगठन की नीतियों को अधिक से अधिक कामगारों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया।

थाना प्रभारी की पहल लाई रंग: जनजागरूकता अभियान से खड़गवां में सड़क हादसों पर लगी लगाम

गांव-गांव पहुंचकर लोगों को किया जागरूक,हेलमेट और यातायात नियमों के पालन से दुर्घटनाओं में आई कमी

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवा,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में सुरक्षित यातायात की आदत विकसित करने के उद्देश्य से खड़गवां थाना पुलिस द्वारा चलाया जा रहा जनजागरूकता अभियान अब सकारात्मक परिणाम देने लगा है, थाना प्रभारी के नेतृत्व में गांव-गांव पहुंचकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिसका असर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी के रूप में सामने आ रहा है, थाना प्रभारी ने केवल चालानी कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय जनसंपर्क और संवाद का रास्ता अपनाया, उन्होंने ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सीधे संवाद कर सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया,अभियान के दौरान युवाओं,वाहन चालकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं,बल्कि स्वयं और दूसरों के जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है।

यातायात नियमों के पालन का दिया संदेश-अभियान के दौरान पुलिस ने हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, तेज रफ्तार से बचने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन नहीं चलाने, ओवरलोडिंग से परहेज करने तथा शराब या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की, लोगों को यह भी समझाया गया कि एक छोटी-सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकती है।

जागरूकता से बदली लोगों की सोच-स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले क्षेत्र में लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं अक्सर सामने आती थीं, लेकिन लगातार चल रहे जागरूकता अभियान के बाद लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा है, अब अधिकतर वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर रहे हैं और यातायात नियमों का पालन करने के प्रति पहले से अधिक सजग हुए हैं।

पुलिस की पहल बनी मिसाल- खड़गवां थाना पुलिस की यह पहल इस बात का उदाहरण बन रही है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई से अधिक प्रभावी परिणाम जनजागरूकता के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, थाना प्रभारी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में सफल साबित हो रहा है,स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे,जिससे सड़क दुर्घटनाओं में और अधिक कमी लाई जा सके तथा क्षेत्र में सुरक्षित यातायात का वातावरण स्थापित हो।

पीजी कॉलेज में पॉश एक्ट व यौन उत्पीडन रोकथाम पर जागरूकता कार्यशाला

विद्यार्थियों ने सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की,सुरक्षित एवं समावेशी परिसर बनाने पर दिया जोर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को यौन उत्पीडन् की रोकथाम,पॉश अधिनियम और विशाखा समिति की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के सोशल इनोवेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट सेल,विशाखा समिति एवं मुहिम फाउंडेशन

के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थियों ने किया। कार्यक्रम की पहल महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं अंकिता, प्रीति, भूमिका, आशुतोष और अंबिके ने की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के बीच किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए,जिसमें परिसर के उन स्थानों की पहचान की गई जहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तरी और संवादात्मक गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कार्यशाला में करीब 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया,जिनमें एनसीसी के कैडेट भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ सामाजिक जागरूकता और व्यक्तित्व विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशाखा समिति की संयोजक डॉ. संगीता पाण्डेय और सोशल इनोवेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट सेल के संयोजक डॉ. दीपक सिंह ने भी अपने विचार रखे। विधि विभाग की डॉ. पूनम ने पॉश अधिनियम,विद्यार्थियों के अधिकारों और शिकायत निवारण की कानूनी प्रक्रिया पर जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में डॉ. कामिनी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. एस.एन. पाण्डेय, डॉ. उमेश कुमार पांडेय,डॉ. माधवेन्द्र तिवारी, डॉ. रजनी सारथी,डॉ. अनुजा कुजूर सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं मुहिम फाउंडेशन के प्रतिनिधि आकृति,रोस और ऋषिकेश उपस्थित रहे।

35 सालों से सावन की शान बना हुआ है अनुराधा पौडवाल का ये शिव भजन

एक-एक लाइन कर देती है भक्ति में लीन

अनुराधा पौडवाल ने भारतीय सिनेमा को कई सदाबहार गानों के साथ-साथ कई यादगार भजन भी दिए हैं जिनमें से एक ये शिव भजन भी है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए एक अलग खुशी लेकर आता है। इस माह में शिव की आराधना के साथ-साथ शिव के भजन भी हर तरफ सुनाई देते हैं। पूजा के साथ संगीत का संगम बरसों से चला आ रहा है और हो भी क्यों ना पूजा के साथ-साथ भजन गाना एक अलग ही अनुभव देता है। वहीं अगर बात पुराने भजनों की हो तो बात ही कुछ और है।मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार और सदाबहार गाने दिए हैं वहीं उनके गाए भजनों को भी कल्ट का दर्जा मिला हुआ है।

सावन की शान बढ़ाता है ये शिव भजन

अनुराधा पौडवाल ने शिव जी के कई भजन गाए लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह उनके गाए सदाबहार भजनों में से एक तो है ही साथ ही यह हर साल सावन की शान भी बढ़ाता है। ये ऐसा भजन है जिसे आपने कहीं ना कहीं,कभी ना कभी जरूर सुना होगा।जिस भजन की हम बात कर रहे हैं उसके बोल हैं- मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा , जिसे अनुराधा पौडवाल ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है। मन मेरा मंदिर...भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीत है, जिसके संगीत निर्देशक दिलीप सेन-समीर सेन हैं और यह एल्बम शिव आराधना का हिस्सा है।

क्या है भजन का भाव?

गाने के बोल में इंसान के दिल की तुलना मंदिर से और शिव की पूजा से की गई है । इस गाने में एक अनोखी पंक्ति है जिसमें देवी पार्वती, सीता का रूप धरकर भगवान राम के पास जाती हैं और शिव की सर्वोच्च महिमा का गुणगान करती हैं। टी-सीरीज के इस भजन को यूट्यूब पर अब तक 479 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने को टी-सीरीज ने 1991 में रिलीज किया था जो शिव आराधना एल्बम का हिस्सा था। इस एल्बम 10 और भजन थे जिसमें मन मेरा मंदिर भी शामिल है। बाकी भजनों में-आओ महिमा गाएं भोले की,चलो शिव के मंदिर में,जय भोले जय भंडारी,जय शिव ओंकारा,शिव शंकर को जिसने पूजा शामिल हैं।

क्राइम-थ्रिलर काट्टालन,ओटीटी रिलीज को तैयार 120 मिनट की फिल्म,कब और कहां होगी स्ट्रीम?

सिनेमाघरों में अक्सर कुछ ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं,जिनकी चर्चा तो कम होती है, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच ये खूब पसंद की जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म अब ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। यहां बात हो रही है एंटनी वर्गीज स्टारर काट्टालन की,जो राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर पेद्दी और बॉबी देओल फेम बंदर के रिलीज होने के एक हफ्ते पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन जिन भी दर्शकों ने ये फिल्म देखी उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की। अब दर्शकों द्वारा प्रशंसित ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक को तैयार है। सिनेमाघरों के बाद अब काट्टालन ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। काट्टालन मूल रूप से मलयालम फिल्म है,लेकिन हिंदी,तमिल,तेलुगु और कन्नड़ डब के साथ भी इसे रिलीज किया गया है और अब ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 8.2 रेटिंग

मिली है। अब जब मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया है तो दर्शकों में जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। मेकर्स ने रिवील किया है कि फिल्म मनोरमा मैक्स पर स्ट्रीम होगी,लेकिन फिलहाल इसकी स्ट्रीमिंग डिटेल का खुलासा नहीं किया गया है।

बात करें काट्टालन की कहानी की तो फिल्म की कहानी हाथी दांत की तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। गांव में हाथियों का आतंक है, जिससे राहत के लिए लोग मारी से मदद मांगने जाते हैं। लेकिन, मदद के बदले मारी पूरे गांव पर अपना कब्जा जमा लेता है और फिर खुलेआम हाथी दांत की तस्करी करता है, जिसके लिए वह हाथियों को मारना शुरू कर देता है। तस्करी के गैर-कानूनी कारोबार में वह गांववालों को भी निशाना बनाने लगता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है पेपे (एंटनी वर्गीज) की, जो स्थानीय ग्रामीणों और जंगलों के इकोसिस्टम के शोषण के खिलाफ खड़ा होता है और मारी के खिलाफ जंग छेड़ देता है।इसकी कहानी पॉल जॉर्ज ने लिखी है और इसके निर्देशन की जिम्मेदारी भी पॉल जॉर्ज ने ही संभाली थी। फिल्म में एंटनी वर्गीज लीड रोल में हैं। उन्होंने फिल्म में पेपे नाम के युवक की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनके साथ सुनील, दुशारा विजयन, पार्थ तिवारी,सिद्दीकी,जगदीश,कबीर दुहान सिंह और हनान शाह जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ 15 करोड़ का कलेक्शन किया था और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद भी इसे आईएमडीबी पर जबरदस्त रेटिंग मिली है।

महारानी सीजन 4 के लिए तैयारी शुरू

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की लोकप्रिय सीरीज महारानी के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। सोनी लिव पर आए इस राजनीतिक ड्रामा में उन्होंने रानी भारती का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी। खबर है कि निर्माताओं ने सीरीज के चौथे सीजन को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य रचनात्मक टीम भी वापस आ रही है। इस हफ्ते से हुमा महारानी सीजन 4 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी।रिपोर्ट के मुताबिक, महारानी सीजन 4 का शूटिंग कार्य 6 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अपने किरदार रानी भारती के रूप में अभिनेत्री फिर से वापसी करेंगी।कुछ वक्त शूटिंग करने के बाद, हुमा थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर आगामी फिल्म टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के प्रचार में जुटेंगी।यश अभिनीत ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें हुमा के अलावा, कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार,टॉक्सिक के प्रचार अभियान के बाद,हुमा बाकी बची शूटिंग पूरी करने के लिए महारानी के सेट पर वापस लौटेंगी। हालांकि,नए सीजन के लिए किसी और कलाकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।कहानी को लेकर भी जानकारी को गुप्त रखा जा रहा है, हालांकि निर्माता जनवरी, 2027 में सीरीज को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।

अखिल अक्किनेनी की फ़िल्म लेनिन की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान...

7 अगस्त से जी5 पर होगी स्ट्रीम

अक्किनेनी प्रिंस अखिल ने हाल ही में रिलीज़ हुई अपनी फ़िल्म लेनिन में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। गौरतलब है कि अखिल ने इस फ़िल्म से बहुत उम्मीदें लगाई थीं क्योंकि उनकी पिछली फ़िल्में बॉक्स ऑफ़िस पर फ़्लॉप रही थीं।लेनिन उनके लिए एक राहत की तरह साबित हुई; क्रिटिक्स ने अखिल की परफ़ॉर्मेंस और मेहनत की तारीफ़ की और इसे अब तक का उनका सबसे बेहतरीन काम बताया। फ़िल्म ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया जब इसने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार किया।इस फ़िल्म में भाग्यश्री बोर्से फीमेल लीड रोल में थीं, जबकि ईश्वरी राव, ब्रह्माजी, प्रमोद पंजू,शत्रु और अन्य कलाकारों ने अहम भूमिकाएँ निभाईं। फ़िल्म का संगीत थमन ने तैयार किया है। अब खबर आ रही है कि फ़िल्म ओटीटी पर रिलीज़ होने के लिए तैयार हैयह फ़िल्म 7 अगस्त 2026 से जी5 ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। मेकर्स ने पोस्टर और यह मैसेज शेयर करके इसकी पुष्टि की : अय्यागारु 7 अगस्त को तेलुगु जी5 पर आ रहे हैं! क्या आप तैयार हैं? लेनिन का प्रीमियर 7 अगस्त को,सिर्फ़ तेलुगु जी 5 पर।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका मीना सिंह पति हरिहर सिंह, जाति क्षत्रिय, निवासी पावर हाउस के पास नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला- नमनाकला, नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर - 13 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 243 / 69 रकबा 6945.49 वर्गफीट भूमि में से रकबा 2400 वर्गफीट भूमि को अपने पुत्र अनावेदक शिवेन्द्र प्रताप सिंह आ0 हरिहर सिंह, जाति क्षत्रिय,निवासी पावर हाउस के पास नमनाकला,अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर के पक्ष में दान करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17.08.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 31.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका निवासी ठनगनपारा, रविशंकर गुप्ता आ0 / पति डॉ0 सुशील प्रसाद गुप्ता जिला अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर,जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला -ठनगनपारा, शीट नम्बर - 3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1466/7 रकबा 0.05 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-17.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-31.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 202601022900011 /अ-27/2025-26

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 202601022900011 /अ-27 / 2025-26 पक्षकार अमोल प्रति अशोक सूर्यवंशी वगै0 में ग्राम मायापुर स्थित कुल खसरा नम्बर 09 कुल रकबा 1.461 हे0 भूमि का फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06/08/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 27/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3**

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 3/9/2026 इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/ विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक साजदा परवीन पति स्व. अब्दुल हमीद, उम्र लगभग 67 वर्ष निवासी वार्ड क्र 02 महगवा सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला - सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1895/2 रकबा क्रमशः1087 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 3/9/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 30/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — **नजूल अधिकारी ,सूरजपुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 3/9/2026 इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक सरवरी बेगम पति स्व. अब्दुल रसीद, निवासी वार्ड क्र 02 महगँवा सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 2894/6 रकबा क्रमशः 2616 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है ।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा /आपत्ति दिनांक 3/9/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 30/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — **नजूल अधिकारी ,सूरजपुर**

न्यायालय नायब तहसीलदार भैयाथान, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 202605260100020/ अ-19/25-26

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सूरजपुर द्वारा अपने पत्र कं. 121 दिनांक 20.03.2026 के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की पुनर्गठन योजना 2025 के तहत जिले में 5 नवीन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का गठन किये जाने के फलस्वरूप ग्राम सावांरावां के नवीन समिति के कार्यालय सह गोदाम निर्माण हेतु ग्राम सांवारावां, तहसील भैयाथान स्थित भूमि खसरा नं0 141 रकबा 8.20 हे0 भूमि का चयन कर कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सूरजपुर के पक्ष में आवंटित करने का निवेदन किया गया है।

अतः इसमें जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित दावा/आपत्ति दिनांक 10/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है नियत तिथी के बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार आज दिनांक 27/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायालय के पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नायब तहसीलदार भैयाथान जिला-सूरजपुर(छ.ग.)**

खेल समाचार

कार्यालय कलेक्टर,जिला सरगुजा एवं पदेन उप सचिव,छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-:: अधिसूचना ::-

अम्बिकापुर दिनांक 30/07/2026

प्र.क्र. / 202603021900001 / 1-82 / 2025-26 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

- अनुसूची -

भूमि का वर्णन -
1. जिला- सरगुजा
2. तहसील - उदयपुर
3. ग्राम / प.ह.न. बडेगांव
4. भूमि का क्षेत्रफल -0.961 हेक्टेयर

खसरा न.	रकबा (हे.में)	खसरा न.	रकबा (हे.में)	खसरा न.	रकबा (हे.में)
160 में से पी–2179	0.400	97	0.004	114	0.016
78	0.016	98	0.020	115	0.008
81	0.012	100	0.024	118	0.020
82	0.032	101	0.004	119/2	0.016
80	0.028	106	0.040	120	0.020
92	0.004	108	0.028	121	0.016
83	0.004	109	0.016	123	0.032
96	0.020	112	0.032	126	0.065
95	0.024	125	0.052	124	0.008
कुल खसरा 27 कुल रकबा 0.961 हे0					

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0-1, अम्बिकापुर
सावजनिक प्रयोजन का विवरण :- बड़ेगांव व्यपवर्तन योजना के डुबान एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु ।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा समाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में दावा / आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिये अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर जिला सरगुजा को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(राम राज सिंह)
भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर

(अजीत बसंत)
कलेक्टर,
सरगुजा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी.नं.-262702512/2

सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। हाल ही में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को लॉज़ेन डायमंड लीग (जिसे एथलेटिसिमा भी कहा जाता है) में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। नीरज यूरोप के स्टार खिलाड़ियों के साथ-साथ एक बहुत ही मज़बूत कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैसा ही होगा। जैवलिन थ्रो के वे पाँच सुपरस्टार जिन्होंने पिछले चार ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीते हैं, वे सभी 21 अगस्त को एथलेटिसिमा में एक शानदार मुकाबले के लिए मौजूद रहेंगे। यह शानदार लाइन-अप दिखाता है कि दुनिया में जैवलिन थ्रो का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप (मौजूदा ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम,भारत के चोपड़ा और श्रीलंका के पाथिराज) और कैरिबियन क्षेत्र (त्रिनिदाद और टोबैगो के वॉलकॉट और ग्रेनाडा के पीटर्स) की ओर कैसे शिफ्ट हुआ है।

भारत की यू-20 पुरुष टीम ने सिंगापुर को हराया

नई दिल्ली,04 अगस्त 2026। बेंगलुरु के सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में खेले गए दो क्लोज्ड-डोर फ्रेंडली मैचों में से पहले मैच में भारत की यू-20 पुरुष टीम ने सिंगापुर को 3-0 से हराया। ऋषि सिंह निंगथौखोंगजाम (45+2 मिनट) और सिंगमायुम शमी (63वें मिनट) ने पहले दो गोल किए,जिसके बाद विपक्षी टीम ने एक ओन गोल (83वें मिनट) किया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सोनकुंवर पति धौकल उम्र 37 वर्ष जाति गोंड निवासी ग्राम कनकपुर पोस्ट नवापाराकला थाना व तहसील प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्री का आधार कार्ड नंबर 681910984353 में नाम प्रियांशु (PRIYANSHU) से बदलकर रांशी (RANSHI) रख लिया है। जो मेरे पुत्री के कक्षा 10वीं के अंकसूची में दर्ज है।

सोनकुंवर
आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग)

ईश्तहार

ई- कोड क्र.../अ-27/2026

सर्व साधारण ग्राम बैकुण्ठपुर राजस्व निरीक्षक बैकुण्ठपुर तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0 तथा हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अफसाना सिद्धिकी पिता स्व0 हाकीम अली उम्र 41 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम- अम्बिकापुर जोड़ा पीपल तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत आवेदन पेश किया कि आवेदिका एवं अनावेदकगण अरशद सिद्धीकी, मोइज अहमद सिद्धिकी, शुल्ताना सिद्धिकी, रिजवाना सिद्धिकी पिता स्व0 हाकीम अली निवासी ग्राम-जुनापारा बैकुण्ठपुर तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0) आपस में भाई- बहन है तथा ग्राम जूनापारा बैकुण्ठपुर के निवासी है। आवेदिका एवं अनावेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की पैतृक भूमि खसरा क0 166/1/क रकबा 0.1360 हे0 एवं खसरा क0 181/ 5 रकबा 0. 0170 हे0 भूमि ग्राम जूनापारा बैकुण्ठपुर प0ह0न0 09 तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में स्थित है। जो संयुक्त खाते में दर्ज है। आवेदिका अपने पैतृक भूमि खसरा क0 166/1/क रकबा 0.1350 हे0 में से 1/5 हिस्सा एवं खसरा क0 181/5 रकबा 0.0170 हे0 में से 02 डिसमिल भूमि को आवेदिका को बंटवारा में प्रदान करते हुए खाता पृथक किया जावे। आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र के साथ खसरा बी 1 नक्शा संलग्न कर बंटवारा किये जाने का आवेदन पेश किया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 18/08/2026 तक स्वयं या अपने प्रतिनिधि अथवा अभिभावक के द्वारा इस न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई बिचार विमर्श नही किया जावेगा।

सील — **तहसीलदार बैकुण्ठपुर जिला कोरिया**

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के माइक स्मिथ को बैटिंग कोच नियुक्त किया

मुंबई ,04 अगस्त 2026। लगातार खराब बैटिंग की समस्या को दूर करने के लिए, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी अगली सीरीज से पहले टेस्ट स्टार असद शफीक की जगह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर माइक स्मिथ को नेशनल टेस्ट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की सोमवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के खिलाफ टीम की आगामी टेस्ट सीरीज़ से कुछ दिन पहले इस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा करने के लिए तैयार है। सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, पीसीबी द्वारा बैटिंग कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी करने के बाद स्मिथ ने इसके लिए आवेदन किया था और वह इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे।

न्यायालय तहसीलदार,अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार जैन आ0 स्व0 जेठमल जैन निवासी कौवाडांड,अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक अशोक कुमार जैन के (पिता) स्व0 जेठमल जैन आ0 स्व. जेठमल जैन की दिनांक 18/02/2024 को स्थान अम्बिकापुर में हुई है।

आवेदक के मृत्यु उपरांत मृत्यु का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 30/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी।

सील — **तहसीलदार अंबिकापुर,जिला-सरगुजा**

न्यायालय तहसीलदार,अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अर्जुन राम आ0 स्व0 लोथेर निवासी परसा थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने दादी (स्व0 टूबो) आ0 धनपत की दिनांक 20/05/1975 को स्थान निवास में हुई है।

आवेदक के मृत्यु उपरांत मृत्यु का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी।

सील — **तहसीलदार अंबिकापुर,जिला-सरगुजा**

C M Y K

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार,सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विकास,आयुष और खाद्य सुरक्षा को मिली नई दिशा

14 नए नर्सिंग कॉलेज, अत्याधुनिक लैब, सीजीएमएससी की बड़ी परियोजनाएं और भ्रामक डेयरी एनालॉग उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध

46 मिनट की प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रखा उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले...छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है...

बस्तर से मेडिकल कॉलेज तक...भर्ती से गुणवत्ता तक...इलाज से खाद्य सुरक्षा तक,स्वास्थ्य विभाग के हर पहलू पर सरकार का दावा...

-न्यूज डेस्क

रायपुर,04 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। लगभग 46 मिनट तक चली प्रेस वार्ता के अंतिम चरण में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा शिक्षा,सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं,आयुष विभाग,खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन के माध्यम से किए जा रहे निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं,बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है।

देश में पहली बार एक साथ पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक साथ पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता को बताया,उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति नहीं मिली है,जबकि छत्तीसगढ़ को एक ही समय में पांच नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की अनुमति मिली,इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना–मनेंद्रगढ़ (एमसीबी),जशपुर (कुनकुरी),दंतेवाड़ा,कवर्धा,जांजगीर-चांपा में की जा रही है,उन्होंने कहा कि इनमें अधिकांश कॉलेज अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं,जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा।

निर्माण कार्य तेज,भर्ती प्रक्रिया शुरू

मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के लिए–भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है,प्रोफेसर एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है,नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां भी की जा रही हैं,उन्होंने विश्वास दिलाया कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने तक आवश्यक फैकल्टी उपलब्ध करा दी जाएगी।

फिजियोथेरेपी शिक्षा को मिला नया विस्तार

मंत्री ने बताया कि राज्य में पहले फिजियोथेरेपी शिक्षा के अवसर सीमित थे,अब सरकार ने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई भी शुरू की जाएगी।

14 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के साथ-साथ प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 14 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया,उन्होंने बताया कि इनमें से 9 नर्सिंग कॉलेजों में इसी वर्ष से पढ़ाई प्रारंभ करने की तैयारी है,इन कॉलेजों की स्थापना–बलरामपुर,पुसौर,दंतेवाड़ा,जांजगीर-चांपा,जशपुर,बैकुंठपुर,नया रायपुर,कुरूद,मनेंद्रगढ़,सरिया,कांकेर,कोरबा,महासमुंद,बीजापुर जैसे क्षेत्रों में की जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा में नई विशेषज्ञता

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नई सुपर स्पेशियलिटी सीटों की भी स्वीकृति मिली है,उन्होंने कहा कि कार्डियक साइंस से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों की अनुमति मिली है,कैंसर सर्जरी (एमसीएच) की सीटों को भी मंजूरी प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा।

जगदलपुर और बिलासपुर में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले गंभीर मरीजों को केवल रायपुर रेफर किया जाता था,अब बिलासपुर में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं,जगदलपुर में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल संचालित हो रहा है,उन्होंने बताया कि यहां हृदय रोग सहित कई जटिल बीमारियों का उपचार शुरू हो चुका है,अब बस्तर के मरीजों को मामूली कारणों से रायपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी।

मेकाहारा अस्पताल के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर

मंत्री ने माना कि रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी अस्पताल है,उन्होंने बताया कि यहां विद्युत व्यवस्था, वातानुकूलन,भवनों की मरम्मत,टाइल्स,आंतरिक एवं बाहरी संरचना,में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं,उन्होंने कहा कि पुराने भवनों को आधुनिक स्वरूप देने का कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है।

आयुष विभाग में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ आयुष पद्धति को भी मजबूत किया जा रहा है,उन्होंने बताया कि–लगभग 502 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं,आयुष चिकित्सकों,योग प्रशिक्षकों,पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है।

400 स्वास्थ्य केंद्रों में योग प्रशिक्षक

उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 400 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है, यहां नियमित योग एवं वेलनेस गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रिकॉर्ड कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई की है,उन्होंने बताया कि नकली पनीर, मिलावटी खोवा,अमानक खाद्य सामग्री, संदिग्ध दवाइयों की लगातार जांच की जा रही है,उन्होंने कहा कि बाजार से नियमित रूप से नमूने लेकर परीक्षण कराया जा रहा है।

भ्रामक डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रतिबंध

प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में जारी उस अधिसूचना का भी उल्लेख किया,जिसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रामक डेयरी एनालॉग एवं अमानक पनीर जैसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है,उन्होंने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

96 करोड़ की आधुनिक प्रयोगशाला बनेगी

मंत्री ने बताया कि लगभग 96 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड लैब बनाई जा रही है,इसमें दवाइयों,खाद्य पदार्थों,पेय पदार्थों, रासायनिक परीक्षण,की आधुनिक जांच की जा सकेगी,उन्होंने कहा कि इससे जांच रिपोर्ट तेजी से उपलब्ध होगी और मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी।

सीजीएमएससी निभा रही दोहरी भूमिका

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन अब केवल दवाइयों और उपकरणों की खरीद तक सीमित नहीं है,यह संस्था-मेडिकल कॉलेज,जिला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज,कैंसर संस्थान,क्रिटिकल केयर यूनिट,बड़े अस्पतालों के भवन का निर्माण भी कर रही है।

700 बिस्तरीय अस्पताल और कैंसर संस्थान

मंत्री ने बताया कि भविष्य की योजनाओं में 700 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल, कैंसर संस्थान,22 क्रिटिकल केयर यूनिट, बिलासपुर सिम्स का आधुनिक परिसर,जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

सिम्स और मेकाहारा का होगा व्यापक विकास

उन्होंने कहा कि बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज का नया परिसर देश के आधुनिक चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा,इसी प्रकार मेकाहारा में भी चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं...

मंत्री ने कहा...कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं,बल्कि उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है,उन्होंने कहा...कि यदि दवा की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी,यदि जांच समय पर नहीं होगी,यदि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे,तो स्वास्थ्य व्यवस्था अधूरी रहेगी,हमारी कोशिश हर स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की है।

प्रेस वार्ता का समापन

अपने संबोधन के अंत में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा...कि पिछले ढाई वर्षों में स्वास्थ्य विभाग ने अधोसंरचना,चिकित्सा शिक्षा,भर्ती,मातृ-शिशु स्वास्थ्य,मलेरिया नियंत्रण,टीबी उन्मूलन,कैंसर उपचार,डायलिसिस,आयुष्मान योजना,आयुष सेवाओं,खाद्य सुरक्षा और दवा गुणवत्ता जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं,उन्होंने कहा...कि सरकार आने वाले समय में भी स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ,आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी, प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और विभागीय कार्यों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

विशेष निष्कर्ष के साथ विशेष श्रृंखला समाप्त

करीब 46 मिनट तक चली इस प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल का विभागवार रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए यह संदेश देने का प्रयास किया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल नई घोषणाओं तक सीमित नहीं है,बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच,गुणवत्ता,चिकित्सा शिक्षा,आपातकालीन उपचार,मातृ एवं शिशु सुरक्षा,आधुनिक जांच सुविधाओं तथा खाद्य सुरक्षा को एक साथ मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तुत आंकड़ों और दावों के माध्यम से सरकार ने यह रेखांकित किया कि उसका लक्ष्य शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करना है।

छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी...समान नागरिक संहिता पर जनता से मांगे गए सुझाव,15 अक्टूबर तक दे सकेंगे राय

रायपुर,04 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के बजाय सभी नागरिकों को संविधान के एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से गठित विशेष समिति ने अब आम जनता और विभिन्न संगठनों से उनके सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। राज्य के नागरिक यह बता सकते हैं कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गठित यह 5-सदस्यीय समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी की आवश्यकता और उसकी रूपरेखा का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों व व्यवस्थाओं की भी व्यापक समीक्षा करेगी। समिति ने शासकीय,गैर-शासकीय संगठनों,सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं,समुदायों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर 2026 तक अपने विचार,राय और अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से जमा करा दें। यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। उत्तराखंड के अलावा गोवा, गुजरात,असम और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है।

सीएम साय की बड़ी घोषणा,माघ पूर्णिमा पर रहेगा सरकारी अवकाश

रायपुर,04 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास के विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं,जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में घोषणा की कि अब हर वर्ष माघ

पूर्णिमा के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दिन प्रदेशभर में शराब और अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री भी पूरी तरह बंद रहेगी। सरकार का उद्देश्य गुरु रविदास के आदर्शों,सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक मूल्यों को सम्मान देना है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। सीएम साय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के राज्य अलंकरण सम्मान में अब एक प्रतिष्ठित पुरस्कार संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी तक उनके संदेश को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)